www.ghoonghatkibagawat
www.ghoonghatkibagawat
ghoonghatkibagawat37@gmail.com
UP/HIN/1999/1282

घूँघट की बगावत

प्रत्येक रविवार को प्रकाशित
हिन्दी साप्ताहिक समाचार पत्र
वर्ष : 24 अंक : 19 गोरखपुर, 17 नवम्बर 2024 रविवार पृष्ठ : 6 मूल्य : 2

आदिवासी भाई-बहनों को नहीं किया जाएगा शामिल, अफवाह फैला रही जेएमएम और कांग्रेस : अमित शाह

मधुपुरा। झारखंड विधानसभा चुनाव को लेकर गृह मंत्री अमित शाह ने मधुपुर विधानसभा क्षेत्र में जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान शाह ने कहा कि झारखंड का ये चुनाव, सिर्फ विधायक चुनने या एक पार्टी की सरकार बदलकर दूसरी पार्टी की सरकार लाने का नहीं है। ये चुनाव, झारखंड के युवाओं, महिलाओं, आदिवासियों व पिछड़ों का भविष्य सुधारने का है। उन्होंने कहा कि झारखंड में परिवर्तन... भ्रष्टाचार को समाप्त करने के लिए चाहिए, घुसपैठियों को रोकने के लिए चाहिए, महिलाओं के खिलाफ हो रहे अपराध को समाप्त करने के लिए चाहिए, आदिवासियों पर हो रहे अत्याचार को रोकने के लिए चाहिए और युवाओं को झारखंड में रोजगार और स्वरोजगार के अवसर दिलाने के लिए चाहिए।

भाजपा नेता ने कहा कि झारखंड, देश का सबसे समृद्ध राज्य है। यहां इतना कोयला और खनिज है कि अकेला झारखंड पूरे देश को खनिज और ऊर्जा दे सकता, लेकिन दुर्भाग्य तो देखिए, झारखंड समृद्ध है और झारखंडी गरीब हैं। मैं आपसे वादा करता हूं, इतने कारखाने झारखंड में लगेंगे कि यहां के युवाओं को नौकरी के लिए अपने परिवार को छोड़कर दूसरे राज्य में पलायन नहीं करना पड़ेगा। शाह ने कहा कि मोदी जी ने देश को सुरक्षित किया, देश को समृद्ध किया। मनमोहन सिंह जी, देश के अर्थतंत्र को 11वें नंबर पर छोड़ कर गए थे। मात्र 10 साल में पीएम नरेन्द्र मोदी ने भारत के अर्थतंत्र को 5वें नंबर पर लाने का काम किया है। वर्ष 2027 तक देश का अर्थतंत्र दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा अर्थतंत्र होगा। इससे पहले दुमका में शाह ने कहा कि झारखंड को बनाने का काम भाजपा के महान नेता, हमारे पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने किया और अब झारखंड को सवांरने का काम प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि कल भगवान बिरसा मुंडा की जयंती थी। दिल्ली के सराय काले खां चौक पर भगवान बिरसा मुंडा की प्रतिमा लगाई गई, जिसका हेमंत बाबू विरोध करते हैं। 2021 में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जी ने भगवान बिरसा मुंडा की जयंती को 'जनजातीय गौरव दिवस' के रूप में मनाने की घोषणा की। इसके साथ ही मोदी जी की अध्यक्षता में एक कमेटी बन रही है और ये कमेटी प्रयास करेगी कि ये पूरा साल (बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती) आदिवासी गौरव वर्ष के रूप में मनाया जाए। अमित शाह ने कहा कि जेएमएम और कांग्रेस ने घुसपैठियों को संरक्षण दिया, जिस कारण से यहां के आदिवासियों की भूमि और जनसंख्या दोनों कम हो रही है। झारखंड में एक बार आप भाजपा की सरकार बना दो, हम एक-एक घुसपैठिए को यहां से बाहर निकालने का काम करेंगे। उन्होंने कहा कि जेएमएम और कांग्रेस, झारखंड में अफवाह फैला रहे हैं कि वउउ आएगी तो आदिवासियों को परेशानी होगी। आदिवासी भाई-बहनों चिंता मत करो, वउउ में आपको शामिल नहीं किया जाएगा। यूसीसी से आपको कोई परेशानी नहीं होगी।

राहुल गांधी ने पीएम मोदी पर संविधान को कमजोर करने का आरोप लगाया

बेरमो । कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने शुक्रवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर संविधान को नष्ट करने की कोशिश करने का आरोप लगाया, जिसे उन्होंने **राष्ट्र की आत्मा** बताया। झारखंड के बेरमो में एक रैली में बोलते हुए गांधी ने उन आरोपों का खंडन किया कि उन्होंने संविधान की ₹झूठी₹ प्रति पेश की थी, उन्होंने कहा कि इसकी विषय-वस्तु महत्वपूर्ण है ।गांधी ने आरोप लगाया कि मोदी ने 16 लाख करोड़ रुपये के औद्योगिक ऋण माफ करके और बुनियादी ढांचे के निजीकरण की घोषणा करके गरीबों की तुलना में अरबपतियों को प्राथमिकता दी है। उन्होंने कहा, ₹उन्होंने उद्योगपतियों के ऋण माफ कर दिए, लेकिन किसानों, दलितों और गरीबों की दुर्दशा को नजरअंदाज कर दिया। गांधी ने यह भी कहा कि जीएसटी और नोटबंदी जैसी नीतियां उच्च बेरोजगारी के लिए जिम्मेदार हैं। कांग्रेस की नीति का खुलासा करते हुए, गांधी ने सत्ता में आने पर जाति जनगणना लागू करने और आरक्षण पर 50% की सीमा हटाने का वादा किया। उन्होंने झारखंड में अनुसूचित जनजातियों (एसटी) के लिए 26% से 28%, अनुसूचित जातियों (एससी) के लिए 10% से 12% और अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) के लिए 14% से 27% आरक्षण का वादा किया। कांग्रेस की कल्याणकारी प्रतिबद्धता को दोहराते हुए, गांधी ने गरीबों, हाशिए पर पड़े समुदायों और युवाओं के उत्थान पर पार्टी के ध्यान पर जोर दिया। उन्होंने मतदाताओं से भाजपा की नीतियों को खारिज करने और समानता और सामाजिक न्याय को प्राथमिकता देने वाली सरकार का समर्थन करने का आग्रह किया।

सीएम योगी के बटेंगे तो कटेंगे नारे का कंगना रनौत ने किया समर्थन

एक ओर जहां यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ के 'बंटेगे तो कंटेगे' नारे पर सियासी बवाल जारी है। वहीं बीजेपी सांसद और अभिनेत्री कंगना रनौत ने इसका समर्थन किया है। उन्होंने कहा कि यह एकता का आह्वान है। हमें बचपन से सिखाया गया है कि एकता ही ताकत है। अगर हम साथ हैं तो सुरक्षित हैं और अगर बंट गए तो कट जाएंगे। उन्होंने कहा कि हमारी पार्टी एक सनातनी पार्टी है, हमारी पार्टी पीओके को भी साथ लेना चाहती है और विपक्ष की बंटवारे की साजिश नाकाम हो रही है। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव से पहले, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा गढ़ा गया नारा, बटेंगे तो कटेंगे, महायुति सहयोगियों के बीच विवाद का एक प्रमुख मुद्दा बन गया है, और राकांपा इसका विरोध कर रही है। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री और भाजपा नेता देवेन्द्र फडणवीस ने राज्य मंत्रिमंडल में अपने सहयोगी और राकांपा नेता अजित पवार के नारे पर विरोध का जवाब देते हुए कहा कि जो लोग हिंदुत्व विरोधी विचारधारा के साथ रहे हैं, उन्हें जनता की भावना को समझने में समय लगेगा। महत्वपूर्ण महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव से पहले अपनी सहयोगी भाजपा को परेशान करते हुए, पवार ने टिप्पणी की थी कि महाराष्ट्र में बटेंगे तो कटेंगे नारे के लिए कोई जगह नहीं है क्योंकि राज्य बीआर अंबेडकर के सिद्धांतों पर काम करता है। पवार की टिप्पणी पर प्रतिक्रिया देते हुए, फड़नवीस ने कहा कि दशकों तक, अजीत पवार ऐसी विचारधाराओं के साथ रहे जो धर्मनिरपेक्ष और हिंदू विरोधी हैं। जो लोग खुद को धर्मनिरपेक्षतावादी कहते हैं उनमें कोई वास्तविक धर्मनिरपेक्षता नहीं है। वह ऐसे लोगों के साथ रहे हैं जिनके लिए हिंदुत्व का विरोध करना धर्मनिरपेक्ष है। जनता का मूड समझने में उन्हें थोड़ा वक्त लगेगा।

झारखंड सरकार की कल्याणकारी योजनाओं के लाभार्थियों की संख्या से भाजपा डरी : कल्पना सोरेन

गांडेय। झारखंड मुक्ति मोर्चा (झामुमो) नेता कल्पना सोरेन ने शुक्रवार को दावा किया कि झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के नेतृत्व वाली सरकार द्वारा शुरू की गई विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के लाभार्थियों की बढ़ती संख्या से भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) डरी हुई है। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि भाजपा खेमे ने लोकप्रिय राज्य सरकार के खिलाफ साजिश रची। गांडेय से विधायक कल्पना ने देवघर जिले के मधुपुर विधानसभा क्षेत्र में एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहा, यह हेमंत (सोरेन) सरकार है, जिसने सर्वजन पेंशन योजना और मंईयां सम्मान योजना लागू की, जिसका उद्देश्य पहली बार महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाना है। उन्होंने कहा कि 55 लाख महिलाओं को पहले ही मंईयां सम्मान योजना के तहत शामिल किया जा चुका है तथा जल्द ही कई और महिलाओं को भी इस योजना के तहत लाया जाएगा।

रिपोर्ट ने किया खुलासा : हिंदुओं का कराया जा रहा जबरन धर्म परिवर्तन

नई दिल्ली। जामिया मिलिया इस्लामिया दिल्ली के प्रमुख विश्वविद्यालयों में से एक है। विश्वविद्यालय अक्सर विवादों में रहता है - कभी दीवाली के दिन हंगामा करने के संबंधित तो कभी राष्ट्र विरोधी प्रदर्शनों से संबंधित। अब एक रिपोर्ट में जामिया मिलिया इस्लामिया विश्वविद्यालय से जुड़े एक महत्वपूर्ण विवाद को उजागर करने का दावा किया है, जो संस्थान में पढ़ने, पढ़ाने या काम करने वाले हिंदुओं के खिलाफ भेदभाव और धमकियों के आरोपों पर केंद्रित है। रिपोर्ट में आरोप लगाया गया है कि जामिया के भीतर एक समूह मौजूद है जो हिंदुओं पर इस्लाम धर्म अपनाने का दबाव बनाता है और मना करने पर उन्हें बलात्कार या पढ़ाई में फेल करने जैसे परिणाम भुगतने की धमकी देता है।

जामिया मिलिया इस्लामिया पर गैर-मुस्लिमों को परेशान करने का आरोप

जामिया मिलिया इस्लामिया विश्वविद्यालय (खटक) एक तथ्य-खोजी समिति की रिपोर्ट के बाद जांच के दायरे में आ गया है। जिसमें गैर-मुस्लिमों के खिलाफ भेदभाव और धर्म परिवर्तन के लिए जबरदस्ती करने के मामलों का आरोप लगाया गया है। एनजीओ ₹कॉल फॉर जस्टिस₹ द्वारा तैयार की गई और प्रमुख कानूनी और प्रशासनिक हस्तियों के नेतृत्व में तैयार की गई रिपोर्ट में संस्थान के भीतर पूर्वाग्रह के एक परेशान करने वाले पैटर्न को उजागर किया गया है। विश्वविद्यालय ने अपने हिस्से के लिए कहा कि पिछले प्रशासन ने ऐसी घटनाओं को गलत तरीके से संभाला हो सकता है, लेकिन वर्तमान प्रशासन एक समावेशी वातावरण बनाने पर केंद्रित था।

रिपोर्ट में गैर-मुस्लिम छात्रों, शिक्षकों और कर्मचारियों के खिलाफ भेदभाव के विवरण सामने आए हैं। गवाहों ने धार्मिक पहचान के आधार पर पूर्वाग्रह और पक्षपात के बारे में गवाही दी, जो कथित तौर पर विश्वविद्यालय के जीवन के विभिन्न पहलुओं में व्याप्त है। अपमानजनक व्यवहार के उदाहरणों को उजागर किया गया, जिसमें एक सहायक प्रोफेसर को मुस्लिम सहकर्मियों से ताने और अपमान का सामना करना पड़ा। एक अन्य घटना में पता चला कि अनुसूचित जाति (एससी) समुदाय के एक गैर-मुस्लिम संकाय सदस्य के साथ असमान व्यवहार किया गया और उन्हें कार्यालय फर्नीचर जैसी बुनियादी सुविधाओं से वंचित रखा गया, जो मुस्लिम समकक्षों को आसानी से प्रदान की जाती हैं।

एक अन्य घटना में परीक्षा के सहायक नियंत्रक शामिल थे, जिनका स्टाफ के सदस्यों द्वारा सार्वजनिक रूप से उपहास किया गया क्योंकि वे एक गैर-मुस्लिम थे और एक वरिष्ठ प्रशासनिक पद पर थे। रिपोर्ट में आदिवासी छात्रों और शिक्षकों द्वारा सामना किए जाने वाले उत्पीड़न के आरोपों पर भी प्रकाश डाला गया है।

इस विषाक्त वातावरण ने कथित तौर पर कई आदिवासी छात्रों को विश्वविद्यालय छोड़ने के लिए मजबूर किया। धर्म परिवर्तन के लिए जबरदस्ती के आरोप भी सामने आए हैं। एक मामले में, एक प्रोफेसर ने कथित तौर पर छात्रों से कहा कि उनकी डिग्री पूरी करना इस्लाम धर्म अपनाने पर निर्भर है, उन्होंने धर्म परिवर्तन के बाद व्यक्तिगत लाभ का हवाला दिया।

जामिया मिलिया इस्लामिया की आधिकारिक प्रतिक्रिया

जामिया मिलिया इस्लामिया विश्वविद्यालय ने आरोपों को संबोधित करते हुए एक बयान जारी किया है, जिसमें समावेशिता को बढ़ावा देने और किसी भी तरह के भेदभाव की निंदा करने की प्रतिबद्धता व्यक्त की गई है। विश्वविद्यालय ने माना कि पिछले प्रशासन ने ऐसी घटनाओं को गलत तरीके से संभाला होगा, लेकिन कुलपति प्रोफेसर मजहर आसिफ के नेतृत्व में न्यायसंगत माहौल बनाने के प्रयासों पर जोर दिया। प्रशासन ने निर्णय लेने और प्रशासनिक भूमिकाओं में हाशिए पर पड़े समूहों को शामिल करने की पहल पर प्रकाश डाला, जैसे कि गैर-मुस्लिम एससी समुदाय के सदस्यों को प्रमुख पदों पर नियुक्त करना। प्रो. आसिफ ने जाति, लिंग या धार्मिक भेदभाव के प्रति अपनी शून्य-सहिष्णुता की नीति दोहराई।

धर्म परिवर्तन के आरोपों का जवाब देते हुए, विश्वविद्यालय ने ऐसे दावों को पुष्ट करने के लिए कोई सबूत होने से साफ इनकार किया। विश्वविद्यालय ने इंडिया टुडे टीवी को बताया अगर कोई ठोस सबूत लेकर आता है, तो हम सख्त कार्रवाई करेंगे। हम शिकायतों के प्रति संवेदनशील हैं और एक सुरक्षित और समावेशी परिसर सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध हैं।

जीत की हैट्रिक लगाने को तैयार बिरंची नारायण

बोकारो। झारखंड की बोकारो विधानसभा सीट पर मुख्य मुकाबला भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस और झारखंड मुक्ति मोर्चा के बीच है। यहां पर वर्तमान विधायक भाजपा के बिरंची नारायण हैं। इस सीट पर 20 नवंबर को मतदान होने हैं। झारखंड विधानसभा चुनाव 2024 दो चरणों में संपन्न होंगे। जिनमे से पहले चरण का चुनाव 13 नवंबर और दूसरे चरण का चुनाव 20 नवंबर को होना है। राज्य में कुल 81 विधानसभा सीटें हैं। राज्य की श्क्द्ध सीटों की बात करें, तो बोकारो विधानसभा सीट भी इनमें से एक है। यह सीट सामान्य सीट है। बोकारो झारखंड के बोकारो जिले में स्थित एक विधानसभा क्षेत्र है। यह सीट धनबाद लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र का हिस्सा है। इस विधानसभा सीट पर मुख्य मुकाबला भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस और झारखंड मुक्ति मोर्चा के बीच है। यहां पर वर्तमान विधायक भाजपा के बिरंची नारायण हैं। बता दें कि राज्य की बोकारो विधानसभा सीट विशेष रूप से आदिवासी बहुल क्षेत्रों में महत्वपूर्म राजनीतिक महत्व रखती है। चुनाव आयोग के आंकड़ों की बात करें, तो साल 2019 के विधानसभा चुनाव के दौरान इस निर्वाचन क्षेत्र में 5,26,660 वोटर थे। जिनमे से पुरुष मतदाताओं की संख्या 2,83,112 थी और महिला मतदाताओं की संख्या 2,43,518 थी। वहीं 30 फीसदी तीसरे जेंडर के मतदाता थे। एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी ने बोकारो सीट से बिरंची नारायण पर भरोसा जताते हुए उन्हें चुनावी मैदान में उतारा है। इससे पहले साल 2019 में भी बिरंची इस सीट से जीत हासिल कर चुके हैं। ऐसे में यह देखना काफी दिलचस्प होगा कि क्या एक बार फिर बिरंची नारायण इस सीट से जीत का फतवा लहरा पाएंगे। पिछले विधानसभा चुनाव के दौरान इस सीट से भाजपा नेता बिरंची नारायण ने मामूली वोटों के अंतर से जीत दर्ज की थी। भाजपा उम्मीदवार को 41.42 प्रतिशत वोट शेयर के साथ जीत हासिल की थी। वहीं बिरंची ने कांग्रेस प्रत्याशी श्वेता सिंह को मात दी थी। कांग्रेस प्रत्याशी श्वेता को 99,020 वोट मिले थे। वहीं अखरव उम्मीदवार राजेंद्र महतो को 14,517 वोटों के साथ तीसरे नंबर पर संतोष करना पड़ा था।

इरफान अंसारी और सीता सोरेन के बीच प्रतिष्ठा की लड़ाई

जामताड़ा। झारखंड विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण का मतदान 20 नवंबर को होना है। ऐसे में राज्य में चुनाव प्रचार जोरों पर है। राज्य की जामताड़ा विधानसभा सीट पर इंडिया गठबंधन की तरफ से इरफान अंसारी कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं। तो वहीं ठऊअ की तरफ से भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर सीता सोरेन चुनावी मैदान में हैं। मुख्य मुकाबला इन्हीं दोनों के बीच माना जा रहा है। हालांकि कुछ निर्दलीय उम्मीदवार भी चुनावी मैदान में हैं। वैसे तो जामताड़ा सीट पर 13 उम्मीदवार चुनावी मैदान में उतरे हैं। जिनमें से कांग्रेस के इरफान अंसारी, झारखंड पीपुल्स पार्टी के अहमद हुसैन, बसपा के आरिफ अंसारी, सीपीआई(एम) के लखनलाल मंडल, बीजेपी की सीता सोरेन, हिंदुस्तान पीपुल्स पार्टी (डेमोक्रेटिक) के कुलदीप यादव, झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा से तरुण कुमार गुप्ता, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (एनसीपी) से बालेश्वर मंडल शामिल हैं। वहीं इस सीट पर निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर मुकेश मुर्मू, रियाद अहमद, अकबर अंसारी, शत्रुघ्न पंडित, सुजीत दास अपनी-अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। लेकिन माना जा रहा है कि ऐसे में कांग्रेस के इरफान अंसारी का खेल खराब हो सकता है। यह सीट दुमका जिले के तहत आती है। यह दुमका लोकसभा क्षेत्र का हिस्सा है। बता दें कि ठगी के मामलों को लेकर जामताड़ा हमेशा चर्चा में बना रहा है। साल 2011 की जनगणना के मुताबिक यहां कि जनसंख्या 29,415 थी। जिनमें से 89 फीसदी हिंदू और 10 फीसदी मुस्लिम थे। जामताड़ा की साक्षरता दर 63.73 फीसदी है। चुनाव आयोग के आंकड़ों के मुताबिक साल 2019 के विधानसभा चुनाव के दौरान जामताड़ा क्षेत्र में 1,65,820 वोटर हैं। जिनमें से 83,310 पुरुष वोटर और 81,723 महिला वोटर हैं। साल 2014 में इस विधानसभा क्षेत्र में वोटरों की संख्या 1,91,876 थी। जिनमें से 99,704 पुरुष वोटर और 91,424 महिला वोटर थीं।

बोरियो सीट पर हमेशा होता आया है कांटे का मुकाबला

बोरियो। झारखंड विधानसभा चुनावों का बिगुल बजने के बाद सभी सियासी दल चुनावी मैदान में उतर चुके हैं। राज्य की 81 विधानसभा सीटों पर 2 चरणों में मतदान होना है। जिनमें से पहले चरण का मतदान 13 नवंबर को संपन्न हो चुका है। तो वहीं दूसरे चरण का मतदान 20 नवंबर को होगा। वहीं 23 नवंबर को चुनावी परिणामों की घोषणा की जाएगी। राज्य के साहेबगंज जिले में पड़ने वाली बोरियो विधानसभा सीट पर भी 20 नवंबर को मतदान होने हैं।

बता दें कि बोरियो विधानसभा सीट पर किसी एक पार्टी का वर्चस्व नहीं रहा है। साल 2000 के चुनाव में यह सीट झामुमो नेता लोबिन हेम्ब्रम ने जीती थी। तो वहीं साल 2005 में इस सीट पर भाजपा नेता ताला मरांडी ने जीत हासिल की थी। वहीं साल 2009 के विधानसभा चुनाव के दौरान लोबिन हेम्ब्रज ने हार का बदला लेते हुए ताला मरांडी को शिकस्त दी थी। 2014 ने भाजपा के टिकट पर ताला मरांडी ने फिर लोबिन ने हराया था। लेकिन साल 2019 में एक बार फिर बाजी पलटी और मरांडी को हेम्ब्रज के सामने शिकस्त खानी पड़ी। साल 2024 के झारखंड विधानसभा चुनावों से ठीक पहले खटट नेता और मौजूदा विधायक लोबिन हेम्ब्रज ने भाजपा का दामन थाम लिया है। वहीं पार्टी ने उसको इसी सीट से टिकट भी दिया है। ऐसे में बोरियो विधानसभा सीट पर मुकाबला बेहद दिलचस्प हो गया है। राज्य में इस समय महागठबंधन की सरकार है और सीएम सोरेन लगातार सत्ता में बने रहने का दावा कर रहे हैं। तो वहीं भाजपा का दावा है कि राज्य की जनता सोरेन सरकार से त्रस्त है और उसको सत्ता से बेदखल करना चाहती है। ऐसे में अब यह देखना काफी दिलचस्प होगा कि इस सीट पर बने समीकरण क्या नया रुख लेते हैं।

आस्था की डुबकी के साथ मनाई गई देव दीपावली

मेरठ। पांडवों की वैभवशाली राजधानी रही हस्तिनापुर में गुरुवार को गंगा के तट से लेकर मंदिर, कुंड, तालाब और घरों में अद्भुत, अलौकिक और दिव्य देव दीपावली मनाई गई। कार्तिक शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी की सुबह श्रद्धालुओं ने पुण्य की डुबकी लगाई। वहीं, शाम के समय गंगा की लहरों पर ऐसा मनोरम दृश्य था, मानों साक्षात देवलोक उतर आया हो। ऐसा भव्य नजारा हस्तिनापुर से लेकर गंगा घाट तक दिखाई दिया। शुक्रवार सुबह गंगा स्नान के मौके पर श्रद्धालु गंगा में स्नान कर अपने अपने गंतव्यों की ओर रवाना हो गए। बताया जाता है कि दीपों की जगमग, झालरों की टिमटिमाती रोशनी, गीत-संगीत की धमक और आतिशबाजी की चमक, फूलों से सजे मंदिर, घाट, चटकीले रंगों से बनी मनोहारी रंगोलियां, घरों से लेकर गंगा के तट तक आस्था का अपार सैलाब और प्राचीन संस्कृति का यह नजारा आकर्षण का केंद्र रहा। कार्तिक मास की पूर्णिमा पर भगवान श्रीकृष्ण की कर्मभूमि हस्तिनापुर का वैभव देखने से लग रहा था कि मानों स्वयं देवता धरा पर आ रहे हों। पतित पावनी मोक्षदायिनी गंगा नदी के जगमगाते घाट और सांस्कृतिक छटा से गंगा की लहरों पर अर्पित दीपों की लड़ियों का अद्भुत नजारा देखने को मिल रहा था। इस नजारे को देखने के लिए काफी संख्या में श्रद्धालु गंगा किनारे पर मौजूद थे।

इन्होंने मां गंगा की पूजा-अर्चना कर मोक्ष की कामना की। मखदूमपुर गंगा घाट, बूढ़ी गंगा घाट सहित द्रौपदी घाट, प्राचीन जयंती माता मंदिर, पांडेश्वर महादेव मंदिर, कर्ण मंदिर, प्राचीन दिगंबर जैन बड़ा मंदिर, श्वेतांबर मंदिर, जंबूदीप तीर्थ आदि दर्जनों स्थान भव्य रूप से दीपमाला और लड़ियों से सजाए गए थे।

सैलाब आस्था का: श्रद्धालुओं ने राप्ती घाट पर लगाई डुबकी

गोरखपुर। कार्तिक पूर्णिमा को धूमधाम से मनाई गई। ब्रह्म बेला में राप्ती नदी के गुरु गोरक्षनाथ घाट, रामघाट, तकिया घाट सहित अन्य घाटों पर श्रद्धालुओं के आस्था का सैलाब उमड़ पड़ा। श्रद्धालुओं ने डुबकी लगाई और श्रद्धानुसार पूजा-अर्चना कर दान-पुण्य किया।

राजघाट पर भोर से ही श्रद्धालुओं के पहुंचने का सिलसिला शुरू हो गया। बच्चे, महिलाएं, बुजुर्ग व नौजवान सभी में स्नान-दान करने की आस्था देखने को मिली। दोपहर तक श्रद्धालु डुबकी लगाते रहे। राप्ती तट पर मेले जैसा माहौल रहा।

दान-पुण्य के साथ गौ-दान भी किए गए। जल में दीये में दीपक जलाकर फूलों से पूजा की व सूर्य को जल दिया। पुरोहित को बुलाकर सत्यनारायण भगवान की कथा सुनी व दान-पुण्य किया।

पुस्तक विमोचन कुटुंब -परिवार ही है संसार

चंडीगढ़। संयुक्त काव्य संग्रह का विमोचन 'कुटुंब परिवार ही है संसार' का विमोचन चंडीगढ़ के राज्य पुस्तकालय सेक्टर 34 में हुआ ।इस अवसर पर कई गणमान्य व्यक्तियों और समाज से सरोकार रखने वाली संस्थाओं के सदस्यों ने शिरकत की ।पुस्तक में अनेक विद्वान लेखकों ने अपना अमूल्य योगदान दिया। इस पुस्तक का प्रमुख उद्देश्य वर्तमान समय में समाज की नींव परिवार संस्था में आए बदलावों और उसको मजबूत करने के लिए विद्वानों ने अनेक विचार पेश कर लोगों का मार्गदर्शन किया। इस पुस्तक के माध्यम से युवा पीढ़ी को परिवार और समाज की अहमियत को समझाने का प्रयास किया है। पुस्तक विमोचन के इस अवसर पर संपादक और लेखक

आदित्य नागरथ परिवार के महत्व पर अपने विचार पेश कियें और समस्त लेखक का धन्यवाद किया। उन्होंने अपनी कविता और कहानियों के माध्यम से परिवार के महत्व और परिवार की जीवन में भूमिका पर अपनी रचनाएं पढ़ी इस अवसर पर राज्य स्तरीय सम्मान से सम्मानित प्रसिद्ध उपन्यासकार यशपाल शर्मा उपस्थित हुए। उन्होंने परिवार में वृद्धो की स्थिति चिंतन करते हुए अपने विचार पेश किये। इस अवसर पर अर्चना ,प्रीति शर्मा 'असीम 'कमलदीप कौर बरियार ,महिपाल सिंह, महेंद्र प्रसाद मौर्य, पूजा उपाध्याय ,रेनू नागर ,शिशुपाल कुमार परिवार के महत्व को दशार्ती अपनी रचनाओं से समाज और जीवन में परिवार के महत्व को दशार्ती अपनी काव्य कृति की प्रस्तुति दी। इस अवसर पर प्रीति शर्मा 'असीम' ने काव्य संग्रह के विषय में अपने विचार व्यक्त करते हुए कहा कि यह संग्रह वर्तमान समय में परिवार के महत्व को और ज्यादा सशक्त करने में सहयोग करेगा ।आज समाज परिवारों के जिस बिखराव से गुजर रहा है ।यह पुस्तक मानव समाज को प्रेरणा देने के लिए मील का पत्थर साबित होगी।

अनमोल प्राकृतिक संसाधनों को विषाक्त होने से बचाएं

जब केन्द्र सरकार जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता कम करने तथा स्वच्छ ऊर्जा को प्रोत्साहन प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है तो देश के अनेक संस्थानों व विभागों को भी पहल की ओर अपने कदम को बढ़ाना चाहिए।

सरकारी प्रयासों के मध्य राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण (नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल- एनजीटी) द्वारा जलवायु व मिट्टी प्रदूषण विस्तारित करने के लिए पानीपत थर्मल पावर स्टेशन पर 6.93 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाना तमाम प्रदूषणक उद्योगो के लिए सबक ही नहीं एक नजीर भी है। ट्रिब्यूनल की कार्रवाई कानूनों का उल्लंघन करके पर्यावरण व जन-स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचाने वालों के लिए संदेश है कि लक्ष्मण रेखा पार की तो खैर नहीं। पर्यावरण को क्षति पहुंचाने पर भारी मुआवजा भी देना होगा। दरअसल, इस थर्मल प्लांट से निकलने वाली एक राख आस-पास के ग्राम-वासियों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ कर रही है जिससे श्वास समेत अनेक प्रकार के रोगों में वृद्धि भी देखी जा रही है। यही नहीं सड़कों पर प्रदूषण के कारण विजिबिलिटी (दृश्यता) भी कम होने से दुर्घटनाओं की आशंका बनी रहती है। वहीं दूसरी ओर एनजीटी ने थर्मल प्लांट के प्रबंधकों द्वारा पर्यावरण की क्षतिपूर्ति के लिए पेड़ों को लगाने में की गई खानापूर्ति को आड़े हाथ लिया। ट्रिब्यूनल का कहना है कि आपने पौधे लगाने का दावा तो किया है लेकिन क्या सुनिश्चित किया है कि उन पौधों से कितने प्रतिशत वृक्ष बन पाए। हरित न्यायाधिकरण का कथन रहा कि पौधारोपण से अधिक महत्त्वपूर्ण पेड़ों की उत्तरजीविता सुनिश्चित करना है। यह उपाय पर्यावरण को हानि पहुंचाने वाले प्रदूषकों के निवारण आधे-अधूरे प्रयासों को ही उजागर करता है।

जलवायु परिवर्तन का दंश झेल रही दुनिया में जनस्वास्थ्य हमारी प्राथमिकता होने के साथ ही प्रदूषण विस्तारक कारकों की सख्त निगरानी एवं कानून के क्रियान्वयन में उदसीनता न आने देने के साथ ही साथ जवाबदेही सुनिश्चित किया जाना भी अनिवार्य है।

निश्चिततौर पर एनजीटी की जुर्माना लगाए जाने संबंधी कार्रवाई प्रदूषण को प्रोत्साहित करने वाली औद्योगिक इकाइयों को अपने तौर-तरीकों को परिवर्तित किए जाने के बाध्य करने की दिशा में एक स्वागतयोग्य कदम है।

उल्लेख्य है कि भारत सरकार ने पिछल्ले एक दशक में तेल व गैस क्षेत्र में राजकोषीय सब्सिडी न्यून करने की दिशा में सार्थक पहल की है लेकिन अभी तक स्वच्छ ऊर्जा से बिजली क्षमता का आधा हिस्सा हासिल करने के महत्वाकांक्षी लक्ष्य प्राप्त करने हेतु वृहतस्तर पर प्रयासों की आवश्यकता महसूस हो रही है। तभी भारत आगामी-2030 तक गैर-जीवाश ईंधन स्त्रोतों से ऊर्जा प्राप्त करने के लक्ष्य को प्राप्त करने में सफल हो पाएगा। जलवायु परिवर्तन सम्मेलन तथा विश्व स्वास्थ्य संगठन लगातार जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता व सब्सिडी कम करने पर बल प्रदान करते रहे हैं। बेशक, स्वच्छ ऊर्जा के स्थाई विकल्पों में निवेश करने से प्रदूषण से उत्पन्न होने वाली बीमारियों पर अंकुश लग सकेगा।

वरूणा संध्या का आयोजन, कलाकारों ने दीं अपनी प्रस्तुतियां

वाराणसी। छावनी परिषद वाराणसी एवं दीपिका कल्चरल सोसाइटी ऑफ इंडिया द्वारा साप्ताहिक आयोजन वरुणा संध्या नेहरू पार्क कैंट में आयोजित किया गया भारत पर्यटन पर्यटन मंत्रालय भारत सरकार के सहयोग से वरुणा संध्या में आज नर्तन इंस्टीट्यूट इन परफॉर्मिंग आर्ट अहमदाबाद की ट्रस्टी व संगीत नाटक अकादमी भारत सरकार द्वारा सम्मानित गुरु स्मिता शास्त्री एवं कलारत्ना के वी सत्यनारायण के द्वारा निर्देशित कुचिपुड़ी नृत्य मे वेणु अयाचित एवं प्रषिता सुराना ने पहली प्रस्तुति गणपतिनि फिर सर्वश्लोकम, सिम्हानंदिनी प्रतुस्त कर रोमांचित कर दिया चौथी प्रस्तुति बाला गोपाल और अंत में भामकलापम पेश कर समाप्त लिया कलाकारों को प्रमाण पत्र एवं स्मृति चिन्ह भेंट दीपिका कल्चरल सोसाइटी ऑफ इंडिया के अध्यक्ष अजय गुप्ता ने प्रदान किया धन्यवाद ज्ञापन छावनी परिषद के अभियंता सचिन कुमार श्रीवास्तव ने ज्ञापित किया ।

ओडीओपी योजनान्तर्गत स्वयं को संवारने में जुटा बीहड़

कानपुर। कभी डकैतों की शरणस्थली के रूप में मशहूर रहा बीहड़ अब देसी घी के रूप में पहचाना जाएगा। एक जिला, एक उत्पाद (ओडीओपी) योजना के तहत बीहड़ को ब्रांड की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है। देसी गाय के दूध से तैयार बीहड़ का घी ई-कॉमर्स (ऑनलाइन) पर मौजूद है। इससे औरैया और इटावा के अलावा बीहड़ और बुंदेलखंड से जुड़े पशुपालकों को फायदा होगा। बीहड़ को भी अलग पहचान मिलेगी। यमुना नदी के किनारे स्थित बीहड़ क्षेत्र के लोग पशुपालन से जुड़े होने की वजह से देसी घी तैयार करने में माहिर थे। हालांकि, वक्त के साथ भट्ठियों पर तैयार देसी घी की जगह फैक्टरियों का सीलबंद देसी घी बाजार में छा गया। लेकिन शुद्धता के कद्रदानों में देसी घी की मांग बनी रही।

ऐसी नौबत क्यों आई

बशीर बद्र का एक शेर है-

दुश्मनी जम कर करो, लेकिन यह गुंजाइश रहे
फिर कभी हम दोस्त बन जायें तो शर्मिंदा न हों।

यह बात हमारे राजनेताओं को समझ क्यों नहीं आती? पिछले चुनाव में महाराष्ट्र के तत्कालीन मुख्यमंत्री ने अपने तब के विरोधी पर भ्रष्टाचार का गंभीर आरोप लगाते हुए भरी सभा में कहा था कि वे उसे जेल भिजवा कर दम लेंगे। उन्होंने यह भी कहा था कि वह राजनेता जेल में ह्यचक्की पीसिंग, पीसिंगह्ल करता रहेगा। आज वह पूर्व मुख्यमंत्री और उनके चक्की पीसिंग वाले मंत्रीजी मंत्रिमंडल में साथ-साथ बैठते हैं! क्या वे दोनों भूल गये हैं कि उन्होंने एक-दूसरे के बारे में क्या-क्या कहा था? और यह ह्यसचह्ल महाराष्ट्र के दो नेताओं का ही सच नहीं है – सारे देश में ऐसे अनेक-अनेक उदाहरण बिखरे पड़े हैं। अक्सर सोचता हूं कि ऐसे लोग जब फिर से दोस्त बन जाते हैं तो एक-दूसरे से आंख कैसे मिलाते होंगे? क्या उन्हें सचमुच शर्म नहीं आती?

यह दुर्भाग्य ही की बात है कि आज हमारी राजनीति में इस तरह की शर्म के लिए कोई स्थान बचा नहीं दिख रहा। शर्म तो इस बात पर भी आनी चाहिए कि हमने राजनीति को पूरी तरह अनैतिक बना दिया है। आज सोच रहा हूं यह बात हंसने की नहीं , दुखी होने की थी। पीड़ा होनी चाहिए थी हमें यह सोच कर कि हमारी राजनीति में नैतिकता के लिए कोई स्थान नहीं बचा। सुनने में अच्छा लगता है यह नारा कि बटेंगे तो कटेंगे। पर पूछा जाना जरूरी है कि क्या सोचकर यह नारा लगाया गया था? किसके बंटने की बात है और कौन किसे काटेगा? उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने यह नारा लगाते हुए बांग्लादेश का नाम लेकर यह स्पष्ट कर दिया था कि वे बहुसंख्यकों और अल्पसंख्यकों की बात कर रहे हैं। धर्म के आधार पर किसी को दुश्मन मान लेना, अपने लिए खतरा मान लेना, किसी भी सभ्य समाज के लिए उचित नहीं माना जा सकता। सवाल हिंदुओं के बंटने का नहीं है, जातियों के बंटने का भी नहीं है, सवाल यह है कि हम किसके लिए बंटने-बांटने की बात कर रहे हैं। इस देश का कोई भी नागरिक, चाहे वह किसी भी धर्म का मानने वाला हो, प्रथमतः भारतीय है। हिंदुओं के एक होने की बात कहने का सीधा-सा मतलब गैर हिंदुओं के खिलाफ एकजुट होने की बात करना है। गलत है यह सोच। कोई भी व्यक्ति सिर्फ इसलिए बुरा नहीं हो सकता कि वह किसी धर्म-विशेष को मानता है। इसका विलोम भी इतना ही सही है। धर्म-विशेष का होने से कोई अच्छा नहीं हो जाता। अच्छा या बुरा होना हमारी करनी और सोच पर निर्भर करता है। पंद्रह लाख रुपए हर भारतीय की जेब में आने वाले वायदे को जब देश के गृहमंत्री ने एक चुनावी जुमला बताया तभी देश को समझ लेना चाहिए था कि राजनेताओं के वादे-दावे भरमाने के लिए ही होते हैं। और यह कोई पहली बार नहीं थी जब देश के किसी नेता ने इस तरह की स्वीकारोक्ति की थी। नेता चाहे किसी भी रंग की टोपी पहनने वाले हों, सब की कथनी एक-सी होती है। चुनाव-दर-चुनाव देश का मतदाता अपने नेताओं द्वारा भरमाया जाता है। कुछ ऐसा ही हाल नेताओं के नारों का भी है। हर चुनाव में नये-नये नारे सुनाई देते हैं, हर चुनाव में नए-नए नारों से नेता हमें भरमाने की कोशिश करते हैं।

ऐसा ही एक नारा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने दिया है। खूब चल रहा है वह नारा। बटेंगे तो कटेंगे के इस नारे को हरियाणा के चुनावों में बाजी पलटने वाला नारा बताया गया था। जब यह नारा पहली बार लगा तो किसी को यह शक नहीं था कि नारा लगाने वाला कहना क्या चाहता है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के मुंह से ही अस्सी और बीस वाली बात देश पहले सुन चुका था। और फिर अपने इस नये नारे के साथ ही ह्यपड़ोस के बांग्लादेश की हालत देख लोह्ल जैसा वाक्य जोड़कर उन्होंने और भी स्पष्ट कर दिया था कि वे हिंदुओं को एकजुट होने का आह्वान कर रहे थे। सवाल हिंदुओं के बंटने का ही नहीं था, इस बात का भी था कि वे किस के खिलाफ एकजुट होने की बात कह रहे हैं। संकेत स्पष्ट था। हरियाणा में यह नारा खूब चला था, अब महाराष्ट्र, झारखंड के चुनावों और उत्तर प्रदेश समेत देश के कई राज्यों में होने वाले उपचुनावों में भी चुनावी सभाओं में यह नारा गूंज रहा है। हां, एक बदलाव जरूर आया है। भाजपा के शीर्ष नेतृत्व ने हिंदुओं के बंटने वाली बात को पिछड़ी जातियों के बंटने से जोड़ दिया है। प्रधानमंत्री का कहना है कि वे लोग यानी कांग्रेसी जातीय जनगणना करा कर पिछड़ी जातियों को बांटने की साजिश रच रहे हैं!

चुनाव-प्रसार में एक-दूसरे पर आरोप लगाना कोई नयी बात नहीं है। सब लगाते हैं इस तरह के नारे। कोई आरोप चिपक जाये तो तीर, वरना तुक्का ही सही! जिस तरह की आरोपबाजी, नारेबाजी चुनावों में होती है, वह हैरान कर देने वाली है। यह बात हमारे भारत तक ही सीमित नहीं है। हाल ही में अमेरिका में हुए राष्ट्रपति पद के चुनाव में एक-दूसरे पर जिस तरह के आरोप लगाये गये वह परेशान करने वाली बात होनी चाहिए। अमेरिका तो दुनिया का सबसे बड़ा जनतंत्र होने का दावा करता है। और हमारा भी दावा है कि सबसे पुराना गणतंत्र है हमारा देश। जनतांत्रिक व्यवस्था में हमारा विरोधी प्रतिद्वंद्वी होता है, दुश्मन नहीं। ऐसे में अनर्गल आरोपों वाली राजनीति उन सबके लिए चिंता की बात होनी चाहिए जो अपने आप को ज़िम्मेदार नागरिक समझते हैं। आरोप लगाना गलत नहीं है। पर आरोप बेबुनियाद नहीं होने चाहिए। साथ ही मयार्दाओं का ध्यान रखा जाना भी जरूरी है। महाराष्ट्र के एक नेता ने राज्य का सबसे बड़ा नेता माने जाने वाले व्यक्ति के चेहरे को निशाना बनाने की घटिया हरकत की थी। अच्छा लगा यह देखकर कि कुछ नेताओं ने इस घटिया हरकत की आलोचना की और उस व्यक्ति ने अपनी करनी पर खेद व्यक्त किया। लेकिन सवाल उठता है यह नौबत क्यों आये?

सार्क की चुनौतियों का समाधान कैसे कर सकता है भारत ?

सार्क के संस्थापक सदस्य के रूप में भारत ने क्षेत्रीय सहयोग के लिए लगातार पहल की है। हालांकि, भारत के प्रयासों के बावजूद, संगठन अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए संघर्ष कर रहा है, जिसके परिणामस्वरूप पिछले कुछ वर्षों में इसकी प्रभावशीलता सीमित रही है। भारत सार्क के भीतर आर्थिक सहयोग, संपर्क और क्षेत्रीय विकास को आगे बढ़ाने में केंद्रीय भूमिका निभाता रहा है। भारत दक्षिण एशियाई मुक्त व्यापार क्षेत्र समझौते में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता रहा है, जिसका उद्देश्य अंतर-क्षेत्रीय व्यापार को बढ़ावा देना था। भारत ने आतंकवाद और सीमा पार खतरों से निपटने के लिए सार्क के प्रयासों का नेतृत्व किया है, जिसमें कई सुरक्षा सहयोग पहलों का प्रस्ताव दिया गया है। भारत ने 1987 में आतंकवाद के दमन पर सार्क क्षेत्रीय सम्मेलन के निर्माण का नेतृत्व किया। हालांकि, इन प्रयासों के बावजूद, कई चुनौतियों के कारण सार्क की प्रभावशीलता सीमित बनी हुई है। साफ्टा के बावजूद, अंतर-सार्क व्यापार 5% से कम बना हुआ है, जो खराब आर्थिक एकीकरण और सार्क की आर्थिक क्षमता को साकार करने में सीमित सफलता को दशार्ता है। आसियान के साथ भारत का व्यापार सार्क देशों के साथ उसके व्यापार से अधिक है, जो महत्वपूर्ण आर्थिक संबंधों को बढ़ावा देने में सार्क की विफलता को रेखांकित करता है। प्रमुख राजनीतिक मतभेदों, विशेष रूप से भारत और पाकिस्तान के बीच, ने शिखर-स्तरीय सहभागिताओं को बाधित किया है, जिससे निर्णय लेने की प्रक्रिया रुक गई है। भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव के कारण 2016 का सार्क शिखर सम्मेलन अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दिया गया था, जो राजनीतिक सामंजस्य के टूटने का संकेत था। सार्क की निर्णय लेने की प्रक्रिया में आम सहमति की आवश्यकता होती है, जिससे पहल धीमी हो गई है, क्योंकि सदस्य देशों के बीच असहमति अक्सर प्रगति को रोक देती है। पाकिस्तान की आपत्तियों के कारण सार्क मोटर वाहन समझौता लागू नहीं हो पाया है, जिससे क्षेत्रीय संपर्क प्रयास रुक गए हैं। भारत और पाकिस्तान के बीच चल रहे भू-राजनीतिक तनाव ने अक्सर सार्क की पहल को पटरी से उतार दिया है और इसकी समग्र प्रभावशीलता को सीमित कर दिया है। 2016 में उरी हमले के कारण भारत ने सार्क शिखर सम्मेलन का बहिष्कार किया, जिससे क्षेत्रीय सहयोग को और झटका लगा। सार्क सदस्यों, विशेष रूप से भारत और छोटी अर्थव्यवस्थाओं के बीच व्यापक आर्थिक मतभेदों ने समान आर्थिक सहयोग हासिल करना चुनौतीपूर्ण बना दिया है। भारत का सकल घरेलू उत्पाद पाकिस्तान के सकल घरेलू उत्पाद से आठ गुना अधिक है, जिससे व्यापार वार्ता और अपेक्षाओं में असंतुलन पैदा होता है। राजनीतिक इच्छाशक्ति और क्षमता की कमी के कारण सार्क समझौतों को अक्सर कार्यान्वयन में महत्वपूर्ण देरी का सामना करना पड़ता है। खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए बनाए गए सार्क खाद्य बैंक का कम उपयोग होने के कारण व्यावहारिक प्रभाव बहुत कम रहा है। कई सार्क देश आर्थिक और रणनीतिक सहायता के लिए चीन जैसी बाहरी शक्तियों पर निर्भर हैं, जिससे सार्क का आंतरिक सहयोग कमजोर हुआ है। नेपाल और श्रीलंका की चीनी बुनियादी ढांचा परियोजनाओं पर बढ़ती निर्भरता ने सार्क की क्षेत्रीय एकता को कमजोर किया है। सार्क के पास निर्णयों को लागू करने या अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए एक मजबूत सुपरनैशनल निकाय का अभाव है, जिससे यह क्षेत्रीय नीतियों को लागू करने में अप्रभावी हो गया है। यूरोपीय संघ के विपरीत, सार्क के पास निर्णयों को लागू करने या विवादों को हल करने के लिए अधिकार रखने वाले संस्थान नहीं हैं। भारत अलग-अलग सार्क सदस्यों के साथ द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने, विश्वास और सहयोग को बढ़ावा देने पर ध्यान केंद्रित कर सकता है जिससे अधिक बहुपक्षीय सफलता मिल सकती है। कनेक्टिविटी और व्यापार पर बांग्लादेश के साथ भारत के हालिया प्रयासों ने सार्क की सीमित प्रगति के बावजूद द्विपक्षीय सहयोग में सुधार किया है। भारत सार्क की निर्णय लेने की प्रक्रिया में सुधार के प्रयासों का नेतृत्व कर सकता है, आम सहमति के बजाय बहुमत आधारित निर्णयों की वकालत कर सकता है, जो अक्सर प्रगति को रोकता है। भारत बिम्सटेक तंत्र के समान सुधारों का प्रस्ताव कर सकता है, जिसने क्षेत्रीय समझौतों में अधिक लचीलापन दिया है। भारत सार्क ढांचे के भीतर व्यापार सुविधा, संपर्क परियोजनाओं और निवेश को बढ़ाकर गहन आर्थिक एकीकरण के लिए प्रयास कर सकता है। बांग्लादेश, भूटान और नेपाल के साथ परिवहन संपर्क पर भारत की बीबीआईएन पहल पाकिस्तान की अनिच्छा को दरकिनार करती है और उप-क्षेत्रीय सहयोग की क्षमता को प्रदर्शित करती है। भारत सार्क देशों के बीच सामाजिक-सांस्कृतिक संबंधों को मजबूत करने के लिए सांस्कृतिक कूटनीति, शैक्षिक आदान-प्रदान और पर्यटन का लाभ उठा सकता है। सदस्य देशों के छात्रों के लिए भारत की सार्क छात्रवृत्ति ने शैक्षणिक और सांस्कृतिक आदान-प्रदान को बढ़ावा दिया है। भारत को बुनियादी ढांचा परियोजनाओं में निवेश जारी रखना चाहिए जो पूरे क्षेत्र में संपर्क को बढ़ाते हैं, व्यापार और लोगों से लोगों के बीच संपर्क को सुविधाजनक बनाते हैं। भारत-नेपाल रेल लिंक परियोजना क्षेत्रीय संपर्क को बेहतर बनाने के लिए भारत की प्रतिबद्धता का उदाहरण है, भले ही सार्क-स्तरीय पहल ठप हो गई हो। संगठन की चुनौतियों के बावजूद सार्क में भारत की महत्वपूर्ण भूमिका सुधार के अवसर प्रस्तुत करती है। द्विपक्षीय सहयोग को बढ़ावा देकर, क्षेत्रीय एकीकरण को बढ़ावा देकर और संरचनात्मक सुधारों को आगे बढ़ाकर, भारत सार्क को पुनर्जीवित कर सकता है और दक्षिण एशिया की स्थिरता और विकास की संभावनाओं को बढ़ा सकता है।

भारत अलग-अलग सार्क सदस्यों के साथ द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने, विश्वास और सहयोग को बढ़ावा देने पर ध्यान केंद्रित कर सकता है जिससे अधिक बहुपक्षीय सफलता मिल सकती है। कनेक्टिविटी और व्यापार पर बांग्लादेश के साथ भारत के हालिया प्रयासों ने सार्क की सीमित प्रगति के बावजूद द्विपक्षीय सहयोग में सुधार किया है। भारत सार्क की निर्णय लेने की प्रक्रिया में सुधार के प्रयासों का नेतृत्व कर सकता है, आम सहमति के बजाय बहुमत आधारित निर्णयों की वकालत कर सकता है, जो अक्सर प्रगति को रोकता है। भारत बिम्सटेक तंत्र के समान सुधारों का प्रस्ताव कर सकता है, जिसने क्षेत्रीय समझौतों में अधिक लचीलापन दिया है। भारत सार्क ढांचे के भीतर व्यापार सुविधा, संपर्क परियोजनाओं और निवेश को बढ़ाकर गहन आर्थिक एकीकरण के लिए प्रयास कर सकता है।

इंटनेट इस्तेमाल करने वाली स्त्रियों की बढ़ती तादाद एक सकारात्मक बदलाव है। लेकिन, इसने और अधिक संख्या में महिलाओं को वर्चुअल दुनिया में खतरों के जोखिम में डाल दिया है। हाँ, ऐसा लग रहा है कि महिलाओं के प्रति ऑनलाइन अपराध की घटनाएँ बढ़ रही हैं। इनमें यौन उत्पीड़न, धमकाने, डराने बलात्कार या जान से मार देने की धमकियाँ देने, साइबर दुनिया में पीछा करने और बिना सहमति के तस्वीरें और वीडियो शेयर करने जैसी वारदातें शामिल हैं। सर्वे में पता चला है कि 60 प्रतिशत लड़कियों और महिलाओं ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर उत्पीड़न का सामना किया है और इनमें से लगभग 20 प्रतिशत ने इसके चलते या तो सोशल मीडिया को अलविदा कह दिया या फिर उसका इस्तेमाल कम कर दिया। भारत की अदालतें, महिलाओं के प्रति ऑनलाइन अपराधों की तुलना में ऑफलाइन जुर्मों को ज्यादा अहमियत देती हैं।

महिलाओं की सुरक्षा और गरिमा के लिए खतरा बनी साइबर की दुनिया

आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से उत्पन्न सामग्री के उदय ने डिजिटल स्पेस में महिलाओं के सामने आने वाली चुनौतियों को और बढ़ा दिया है, जिससे ऑनलाइन उत्पीड़न और गोपनीयता उल्लंघन के नए रूप सामने आए हैं। इसने टेक कंपनियों और सरकारों दोनों को तत्काल कार्यवाही करने की आवश्यकता बताई है। आज जब साइबर क्षेत्र में महिलाओं के लिए खतरे कई गुना बढ़ गए हैं, तो ऐसा कोई सुरक्षित ठिकाना नहीं बचा है, जहाँ वह छुप सकें और न ही कोई कड़ी सुरक्षा वाला इलाका है, जहाँ बैठकर वह अपने सम्मान पर डाका डालने वाले साइबर खतरों के खत्म होने का इंतजार कर सकें। एक वैश्विक सर्वे में पता चला है कि 60 प्रतिशत लड़कियों और महिलाओं ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर उत्पीड़न का सामना किया है और इनमें से लगभग 20 प्रतिशत ने इसके चलते या तो सोशल मीडिया को अलविदा कह दिया या फिर उसका इस्तेमाल कम कर दिया। इसी तरह यूएन विमेन ने पाया है कि दुनिया भर में 58 प्रतिशत महिलाएँ और लड़कियों को किसी न किसी तरह के ऑनलाइन शोषण का शिकार होना पड़ा है। इनमें ट्रोलिंग, पीछा करने, डॉक्सिंग और लैंगिकता पर आधारित दूसरे तरह के ऑनलाइन हिंसक बर्ताव हैं, जो डिजिटिल युग के नए खतरों के तौर पर उभर रहे हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग डीपफेक वीडियो और चित्र बनाने के लिए किया जा रहा है, जो महिलाओं को मनगढ़ंत सामग्री के साथ लक्षित करते हैं जो अक्सर प्रकृति में यौन या मानहानिकारक होती है। यू।एस। की उपराष्ट्रपति कमला हैरिस को 2024 के राष्ट्रपति पद के लिए अपने अभियान के दौरान झूठे और हानिकारक संदर्भों में उन्हें चित्रित करने वाले डीपफेक का सामना करना पड़ा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल महिलाओं के चरित्र और विश्वसनीयता को कम करने के लिए डिजाइन की गई झूठी कथाएँ या स्त्री-द्वेषी सामग्री फैलाते हैं, विशेष रूप से नेतृत्व की भूमिकाओं में महिलाओं को लक्षित करते हैं। रिपब्लिकन प्राइमरी के दौरान निक्की हेली हेरफेर की गई छवियों और फजी खबरों का शिकार हुईं। महिलाओं को ऑनलाइन वस्तुकरण और यौन रूप से स्पष्ट सामग्री का असंगत स्तर का सामना करना पड़ता है, जो वास्तविक नकली सामग्री बनाने की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्षमता द्वारा बढ़ाया जाता है। इतालवी प्रधान मंत्री जियोर्जिया मेलोनी की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस द्वारा बनाई गई स्पष्ट तस्वीरें सोशल मीडिया पर व्यापक रूप से प्रसारित हुईं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस द्वारा बनाई गई डीपफेक और बदली हुई तस्वीरें महिलाओं की निजता का उल्लंघन करती हैं, जिसके परिणामस्वरूप अक्सर प्रतिष्ठा को काफी नुकसान होता है और मानसिक परेशानी होती है। बांग्लादेशी राजनेता रूमिन फरहाना को चुनावों से पहले डीपफेक सामग्री के साथ निशाना बनाया गया था। तकनीकी कंपनियों और सरकारों द्वारा समस्या को कम करने के लिए कदम। कंपनियों को त्रुटियों को रोकने के लिए मानवीय निगरानी के साथ, हानिकारक सामग्री को व्यापक रूप से प्रसारित होने से पहले सक्रिय रूप से चिह्नित करने और हटाने के लिए उन्नत आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डिटेक्शन सिस्टम में निवेश करना चाहिए।

मेटा (फेसबुक) ने हाल ही में डीपफेक से निपटने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल की घोषणा की, लेकिन उनका कार्यान्वयन असंगत बना हुआ है। प्लेटफॉर्म को स्पष्ट जवाबदेही उपाय प्रदान करने चाहिए और रिपोर्ट करनी चाहिए कि वे अपनी मॉडरेशन नीतियों के पारदर्शी ऑडिट के साथ फ़्लैग की गई सामग्री को कैसे संभालते हैं। यूरोपीय संघ के डिजिटल सेवा अधिनियम (2022) में डिजिटल प्लेटफॉर्म को सामग्री मॉडरेशन क्रियाओं की रिपोर्ट करना अनिवार्य किया गया है। तकनीकी कंपनियों को यह सुनिश्चित करने की आवश्यकता है कि एल्गोरिदम को इस तरह से डिजाइन किया जाए कि लिंग पूर्वाग्रह कम हो और हानिकारक उद्देश्यों के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल का दुरुपयोग रोका जा सके। गूगल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिद्धांत आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ज़िम्मेदार उपयोग पर प्रकाश डालते हैं, लेकिन अधिक कार्यान्वयन की आवश्यकता है। सरकारों को डेटा सुरक्षा कानूनों को लागू करना चाहिए और डीपफेक-विशिष्ट कानूनों सहित एआई-जनरेटेड सामग्री के दुरुपयोग को सम्बोधित करने के लिए विशिष्ट कानूनी प्रावधान बनाने चाहिए। भारत के सूचना प्रौद्योगिकी (मध्यवर्ती दिशानिर्देश और डिजिटल मीडिया आचार संहिता) नियम 2021 सामग्री मॉडरेशन के लिए एक रूपरेखा प्रदान करता है, लेकिन इसमें कड़े एआई-विशिष्ट नियमों का अभाव है। सरकारों को एआई नैतिकता बोर्ड और रूपरेखाएँ स्थापित करनी चाहिए जो नैतिक एआई विकास को अनिवार्य बनाती हैं, लिंग आधारित भेदभाव को रोकने पर ध्यान केंद्रित करती हैं। यूरोपीय संघ के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अधिनियम का उद्देश्य उच्च जोखिम वाली एआई प्रणालियों को विनियमित करना है, विशेष रूप से मीडिया और निगरानी में। सरकारों को डीपफेक सामग्री की पहचान करने और रिपोर्ट करने के लिए जन जागरूकता अभियान शुरू करना चाहिए, विशेष रूप से कमजोर समूहों को लक्षित करना चाहिए।

भारत का राष्ट्रीय साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल एआई-जनरेटेड कंटेंट से जुड़े साइबर अपराधों की आसान रिपोर्टिंग की सुविधा देता है। निर्धारित समय सीमा के भीतर हानिकारक कंटेंट को हटाने में विफल रहने पर तकनीकी कंपनियों को मौद्रिक दंड के माध्यम से जवाबदेह ठहराया जाना चाहिए। यूरोपीय संघ में जीडीपीआर उन कंपनियों पर भारी जुमार्ना लगाने की अनुमति देता है जो उपयोगकताओं को डेटा के दुरुपयोग से बचाने में विफल रहती हैं। सरकारों, तकनीकी फर्मों और नागरिक समाज के बीच एक सक्रिय, बहुपक्षीय दृष्टिकोण महिलाओं के लिए सुरक्षित डिजिटल स्थानों का निर्माण सुनिश्चित करेगा, नैतिक एआई विकास और मजबूत ऑनलाइन सुरक्षा को बढ़ावा देगा।

-प्रियंका सौरभ

बाजारीकरण की भेंट चढ़े हमारे सामाजिक त्यौहार

कृषि प्रधान होने के कारण प्रत्येक ऋतु-परिवर्तन हंसी-खुशी मनोरंजन के साथ अपना-अपना उपयोग रखता है। इन्हीं अवसरों पर त्यौहार का समावेश किया गया है, जो उचित है। प्रथम श्रेणी में वे व्रतोत्सव, पर्व-त्यौहार और मेले है, जो सांस्कृतिक हैं और जिनका उद्देश्य भारतीय संस्कृति के मूल तत्वों और विचारों की रक्षा करना है। इस वर्ग में हिन्दूओं के सभी बड़े-बड़े पर्व-त्यौहार आ जाते है, जैसे-होलिका-उत्सव, दीपावली, बसन्त, श्रावणी, संक्रान्ति आदि। संस्कृति की रक्षा इनकी आत्मा है। दूसरी श्रेणी में वे पर्व-त्यौहार आते है, हिन्हें किसी महापुरूष की पुण्य स्मृति में बनाया गया है। जिस महापुरूष की स्मृति के ये सूचक है, उसके गुणों, लीलाओं, पावन चरित्र, महानताओं को स्मरण रखने के लिए इनका विधान है। इस श्रेणी में रामनवमी, कृष्णाष्टमी, भीष्म-पंचमी, हनुमान-जयंती, नाग-पंचमी आदि त्यौहार रखे जा सकते हैं। यानि यहाँ हर दिन में एक त्यौहार अवश्य पड़ता है। अनेकता में एकता की मिसाल इसी त्यौहार पर्व के अवसर पर देखी जाती है। रोजमर्रा की भागती-दौड़ती, उलझनों से भरी हुई ऊर्जा प्रधान हो चुकी, वीरान-सी बनती जा रही जिन्दगी में ये त्यौहार ही व्यक्ति के लिए सुख, आनंद, हर्ष एवं उल्लास के साथ ताजगी भरे पल लाते हैं। यह मात्र हिंदू धर्म में ही नहीं वरन विभिन्न धर्मों, संप्रदायों पर लागू होता है। वस्तुतः ये पर्व विभिन्न जन समुदायों की सामाजिक मान्यताओं, परंपराओं और पूर्व संस्कारों पर आधारित होते हैं। सभी त्यौहारों की अपनी परंपराएँ, रीति-रिवाज होते हैं। ये त्यौहार मानव जीवन में करुणा, दया, सरलता, आतिथ्य सत्कार, पारस्परिक प्रेम, सद्भावना, परोपकार जैसे नैतिक गुणों का विकास कर मनुष्य को चारित्रिक एवं भावनात्मक बल प्रदान करते हैं। भारतीय संस्कृति के गौरव एवं पहचान ये पर्व, त्यौहार सामाजिक, धार्मिक, सांस्कृतिक एवं आध्यात्मिक दृष्टि से अति महत्त्वपूर्ण हैं। सामाजिक त्यौहार और अंतर-विद्यालय सांस्कृतिक कार्यक्रम बच्चों के आत्मविश्वास और पारस्परिक कौशल के निर्माण में सहायता करने के लिए अद्भुत अवसर प्रदान करते हैं। पारस्परिक कौशल में दूसरों के साथ प्रभावी ढंग से संवाद करने और बातचीत करने की क्षमता शामिल है और आत्मविश्वास स्वयं और स्वयं की क्षमताओं में विश्वास है, जो दोनों दूसरों के साथ सकारात्मक सम्बंध बनाने के लिए आवश्यक हैं। इस लेख में, हम कुछ तरीकों पर गौर करेंगे कि ये आयोजन बच्चों के आत्मविश्वास और पारस्परिक कौशल को बनाने में कैसे मदद करते हैं। सामाजिक त्यौहार विभिन्न संस्कृतियों, भाषाओं और परंपराओं के संपर्क में लाते हैं, जो उनके क्षितिज को व्यापक बना सकते हैं और उन्हें दूसरों के प्रति सहानुभूति और समझ विकसित करने में मदद कर सकते हैं। नए दोस्त और संपर्क बना सकते हैं, जो समुदाय से अधिक जुड़ाव महसूस करने और अपनेपन की भावना विकसित करने में मदद कर सकते हैं। ये आयोजन इसे विकसित करने का एक शानदार तरीका है क्योंकि वे बहुत सारे लोगों को एक साथ लाते हैं और इस तरह एकता और भाईचारे की भावना पैदा करते हैं। ये जीवन के विभिन्न क्षेत्रों के लोगों के प्रति अधिक स्वीकार्य, सहिष्णु और समावेशी होना सिखाते हैं।

हिंदुस्तान त्योहारों का देश है। त्यौहार हमको सामाजिक और संस्कारिक रूप से जोड़ने का काम करते हैं। हमारी सांस्कृतिक और संस्कारिक एकता ही भारत की अखंडता का मूल आधार है। व्रत-त्यौहारों के दिन हम देवताओं का स्मरण करते हैं, व्रत, दान तथा कथा श्रवण करते हैं, जिससे व्यक्तिगत उन्नति के साथ सामाजिक समरसता का संदेश भी समाज में पहुँचता है। इसमें ही भारतीय संस्कृति के बीज छिपे हैं। हमारे सामाजिक जीवन में कुछ ऐसे दिन आते हैं जिनसे मात्र एक व्यक्ति, या परिवार ही नहीं वरन पूरा समाज आनंदित और उल्लासित होता है। भारत को यदि पर्व-त्योहारों का देश कहा जाए तो उचित होगा। यहाँ भोजपुरी भाषा में एक कहावत है-'सात वार नौ त्यौहार'।

बाजारीकरण ने सारी व्यवस्थाएँ बदल कर रख दी है। हमारे उत्सव-त्योहार भी इससे अछूते नहीं रहे। शायद इसीलिए प्रमुख त्यौहार अपनी रंगत खोते जा रहे हैं और लगता है कि हम त्यौहार सिर्फ.औपचारिकताएँ निभाने के लिए मनाये जाते हैं। किसी के पास फुरसत ही नहीं है कि इन प्रमुख त्योहारों के दिन लोगों के दुख दर्द पूछ सकें। सब धन कमाने की होड़ में लगे हैं। गंदी हो चली राजनीति ने भी त्योहारों का मजा किरकिरा कर दिया है। हम सैकड़ों साल गुलाम रहे। लेकिन हमारे बुजुर्गों ने इन त्योहारों की रंगत कभी फीकी नहीं पड़ने दी। आज इस अर्थ युग में सब कुछ बदल गया है। कहते थे कि त्यौहार के दिन न कोई छोटा और न कोई बड़ा। सब बराबर। लेकिन अब रंग प्रदर्शन भर रह गये हैं और मिलन मात्र औपचारिकता। हम त्यौहार के दिन भी हम अपनो से, समाज से पूरी तरह नहीं जुड़ पाते। जिससे मिठाइयों का स्वाद कसैला हो गया है। बात तो हम पूरी धरा का अँधेरा दूर करने की करते हैं, लेकिन खुद के भीतर व्याप्त अंधेरे तक को दूर नहीं कर पाते। त्योहारों पर हमारे द्वारा की जाने वाली इस रस्म अदायगी शायद यही इशारा करती है कि हमारी पुरानी पीढियों के साथ हमारे त्यौहार भी विदा हो गये।

हमारे पर्व त्यौहार हमारी संवेदनाओं और परंपराओं का जीवंत रूप हैं जिन्हें मनाना या यूँ कहें की बार-बार मनाना, हर साल मनाना हर समाज बंधु को अच्छा लगता है। इन मान्यताओं, परंपराओं और विचारों में हमारी सभ्यता और संस्कृति के अनगिनत सरोकार छुपे हैं। जीवन के अनोखे रंग समेटे हमारे जीवन में रंग भरने वाली हमारी उत्सवधर्मिता की सोच मन में उमंग और उत्साह के नये प्रवाह को जन्म देती है। हमारा मन और जीवन दोनों ही उत्सवधर्मी है। हमारी उत्सवधर्मिता परिवार और समाज को एक सूत्र में बाँधती है। संगठित होकर जीना सिखाती है। सहभागिता और आपसी समन्वय की सौगात देती है। हमारे त्योहार, जो हम सबके जीवन को रंगों से सजाते हैं, सामाजिक त्यौहार एक अनूठा मंच प्रदान करते हैं इनमे साथियों के साथ सहयोग करने, मिलने और सामूहीकरण करना, अपनी प्रतिभा दिखाने और विभिन्न संस्कृतियों और परंपराओं के बारे में सिखाने और सीखने की क्षमता होती है। ये कौशल हमारे जीवन का एक अनिवार्य हिस्सा हैं और अक्सर हमारे जीवन के लगभग सभी पहलुओं के मूल में होते हैं। इसलिए, वर्तमान समय में इनकी प्रासंगिकता का जहाँ तक प्रश्न है, व्रत-त्यौहारों के दिन हम उक्त देवता को याद करते हैं, व्रत, दान तथा कथा श्रवण करते हैं जिससे व्यक्तिगत उन्नति के साथ सामाजिक समरसता का संदेश भी दिखाई पड़ता है। इसमें भारतीय संस्कृति के बीज छिपे हैं। ₹ पर्व त्यौहारों का भारतीय संस्कृति के विकास में अप्रतिम योगदान है। भारतीय संस्कृति में व्रत, पर्व-त्यौहार उत्सव, मेले आदि अपना विशेष महत्त्व रखते हैं। हिंदुओं के ही सबसे अधिक त्यौहार मनाये जाते हैं, कारण हिन्दू ऋषि-मुनियों के रूप में जीवन को सरस और सुन्दर बनाने की योजनाएँ रखी है। प्रत्येक पर्व-त्यौहार, व्रत, उत्सव, मेले आदि का एक गुप्त महत्त्व हैं। प्रत्येक के साथ भारतीय संस्कृति जुडी हुई है। वे विशेष विचार अथवा उद्देश्य को सामने रखकर निश्चित किये गये हैं। मूल्यों को पुनः प्रतिष्ठा के लिए मूल्यपरक शिक्षा की आवश्यकता पर विशेष बल दिया गया है। मूल्यपरक शिक्षा आज समय की मांग बन गई है। अतः इसे शीघ्रतिशीघ्र लागू करने की आवश्यकता है। वर्तमान डिजिटल युग में लोग अपनी सभ्यता-संस्कृति को भूलते जा रहे हैं। इसके कारण व्रत तथा त्यौहार का महत्त्व बढ़ जाता है।

–डॉ. सत्यवान 'सौरभ'

जख्म हो जाते गहरे

जाने क्या सोच कर दिल सहम जाता
जाने क्यों मन मे अब वहम आ जाता
टूटकर बिखर गये आँखों से अश्क भी
पावन कर गये नयन को अब इश्क भी
ना सुकून है कंही ना ही कंही चैन है
हर पल दिल भी रहता सदा बेचैन है
कैसी कशिश साथ और अहसास भी
कैसा सफर मिलता है जहाँ रश्क भी
ये क्या हो गया है कुछ पता भी नहीं
दुनियाँ से खुशियाँ लापता ही सही
सफर तो सफर है ये सफर ही रहेगा
कैसा सफर मिलता है जहाँ पुष्क भी
बस सफर है जारी तो सफर कीजिए
अभी बस वर्तमान का मजा लीजिए
चार दिन मेला है जगा का झमेला भी
जख्म हो जाते गहरे बहते अश्क भी
मौसम का मिजाज भले बदलता रहा
सफर दर सफर बस मै चलता ही रहा
सफर का अंजाम हो भले चाहे जो भी
मौसम मिजाज चाहे कितना शुष्क भी

प्रमेशदीप मानिकपुरी
आमाचानी धमतरी छ ग

साइबर क्राइम क्या है? प्रकार, उदाहरण और रोकथाम

'साइबर क्राइम' शब्द कंप्यूटर उद्योग और नेटवर्क में नवीनतम विकास के बाद पेश किया गया था। साइबर अपराधों को एक बड़ा जोखिम माना जाता है क्योंकि उनके वित्तीय नुकसान, संवेदनशील डेटा का उल्लंघन, सिस्टम की विफलता जैसे विनाशकारी प्रभाव हो सकते हैं, और यह किसी संगठन की प्रतिष्ठा को भी प्रभावित कर सकता है। साइबर क्राइम क्या है? साइबर अपराध को ₹किसी भी गैरकानूनी कार्य को करने या करने में सहायता करने के लिए किसी भी संचार उपकरण का अवैध उपयोग₹ के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। साइबर अपराध को एक प्रकार के अपराध के रूप में समझाया जाता है जो नुकसान के उद्देश्य से एक नेटवर्क के तहत कंप्यूटर या कंप्यूटर के समूह को लक्षित या उपयोग करता है। साइबर अपराध कंप्यूटर और कंप्यूटर नेटवर्क का उपयोग करके किए जाते हैं। वे व्यक्तियों, व्यावसायिक समूहों या यहां तक कि सरकारों को भी निशाना बना सकते हैं। जांचकर्ता उन उपकरणों की जांच करने के लिए विभिन्न तरीकों का उपयोग करते हैं जिनके इस्तेमाल होने या साइबर अपराध का लक्ष्य होने का संदेह होता है। साइबर अपराधी कौन हैं? साइबर अपराधी वह व्यक्ति होता है जो प्रौद्योगिकी में अपने कौशल का उपयोग दुर्भावनापूर्ण कार्यों और अवैध गतिविधियों को करने के लिए करता है जिन्हें साइबर अपराध के रूप में जाना जाता है। वे व्यक्ति या टीम हो सकते हैं. साइबर अपराधी व्यापक रूप से ₹डार्क वेब₹ में उपलब्ध हैं, जहां वे ज्यादातर अपनी अवैध सेवाएं या उत्पाद प्रदान करते हैं। प्रत्येक हैकर साइबर अपराधी नहीं है क्योंकि हैकिंग को स्वयं अपराध नहीं माना जाता है क्योंकि इसका उपयोग कमजोरियों को रिपोर्ट करने और उन्हें बैचने के लिए किया जा सकता है जिसे ₹व्हाइट हैट हैकर₹ कहा जाता है। हालाँकि, हैकिंग को एक साइबर अपराध माना जाता है जब इसका कोई हानिकारक गतिविधियों को संचालित करने का दुर्भावनापूर्ण उद्देश्य होता है और हम इसे ₹ब्लैक हैट हैकर₹ या साइबर-अपराधी कहते हैं। साइबर अपराधियों के पास हैकिंग कौशल होना आवश्यक नहीं है क्योंकि सभी साइबर अपराधों में हैकिंग शामिल नहीं है। साइबर अपराधी ऐसे व्यक्ति हो सकते हैं जो अवैध ऑनलाइन सामग्री का व्यापार कर रहे हों या घोटालेबाज या यहां तक कि ड्रग डीलर भी हो सकते हैं। तो यहां साइबर अपराधियों के कुछ उदाहरण दिए गए हैंः - ब्लैक हैट हैकर्स - साइबरस्टॉकर्स - साइबर आतंकवादी - घोटालेबाज लक्षित हमले करने वाले साइबर अपराधियों को थ्रेट एक्टर्स कहा जाना बेहतर है। साइबर अपराध कैसे होते हैं? साइबर अपराधी सिस्टम में पाए जाने वाले सुरक्षा छिद्रों और कमजोरियों का फायदा उठाते हैं और लक्षित वातावरण में पैर जमाने के लिए उनका फायदा उठाते हैं। सुरक्षा छेद कमजोर प्रमाणीकरण विधियों और पासवर्ड का उपयोग करने का एक रूप हो सकता है, यह सख्त सुरक्षा मॉडल और नीतियों की कमी के कारण भी हो सकता है। साइबर अपराध क्यों बढ़ रहे हैं? दुनिया लगातार नई-नई तकनीक विकसित कर रही है, इसलिए अब उसकी निर्भरता तकनीक पर बहुत ज्यादा हो गई है। अधिकांश स्मार्ट डिवाइस इंटरनेट से जुड़े होते हैं। इसके फायदे भी हैं और जोखिम भी हैं. जोखिमों में से एक साइबर अपराधों की संख्या में बड़ी वृद्धि है, इन प्रौद्योगिकियों की सुरक्षा में मदद करने के लिए पर्याप्त सुरक्षा उपाय और संचालन नहीं हैं। कंप्यूटर नेटवर्क साइबरस्पेस में लोगों को सेकंडों में दुनिया के किसी भी जुड़े हिस्से तक पहुंचने की अनुमति देता है। साइबर अपराधों के लिए एक देश से दूसरे देश में अलग-अलग कानून और नियम हो सकते हैं, यह भी उल्लेख करते हुए कि वास्तविक अपराधों के बजाय साइबर अपराध करते समय ट्रैक को कवर करना बहुत आसान होता है। हम साइबर अपराधों में बड़ी वृद्धि के विभिन्न कारणों को नीचे सूचीबद्ध कर रहे हैंः - कमजोर उपकरणः जैसा कि हमने पहले उल्लेख किया है, कुशल सुरक्षा उपायों और समाधानों की कमी से कमजोर उपकरणों की एक विस्तृत श्रृंखला सामने आती है जो साइबर अपराधियों के लिए एक आसान लक्ष्य है। - व्यक्तिगत प्रेरणाः साइबर अपराधी कभी-कभी किसी से बदला लेने के लिए साइबर अपराध करते हैंनफरत है या कोई समस्या है. - वित्तीय प्रेरणाः साइबर अपराधियों और हैकर समूहों की सबसे आम प्रेरणा, आजकल अधिकांश हमले इससे लाभ कमाने के लिए किए जाते हैं। साइबर अपराध के दो मुख्य प्रकार - कंप्यूटर को निशाना बनाना इस प्रकार के साइबर अपराधों में हर संभव तरीका शामिल है जो कंप्यूटर उपकरणों को नुकसान पहुंचा सकता है, उदाहरण के लिए मैलवेयर या सेवा से इनकार करने वाले हमले। - कंप्यूटर का उपयोग करना इस प्रकार में कंप्यूटर अपराधों के सभी वर्गीकरण करने के लिए कंप्यूटर का उपयोग शामिल है। साइबर अपराधों का वर्गीकरण साइबर अपराधों को सामान्यतः चार श्रेणियों में वगीर्कृत किया जा सकता हैः 1. व्यक्तिगत साइबर अपराधः यह प्रकार व्यक्तियों को लक्षित कर रहा है। इसमें फि शिंग, स्पूफि ंग, स्पैम, साइबरस्टॉकिंग और बहुत कुछ शामिल है। 2. संगठन साइबर अपराधः यहां मुख्य लक्ष्य संगठन हैं। आमतौर पर, इस प्रकार का अपराध अपराधियों की टीमों द्वारा किया जाता है जिसमें मैलवेयर हमले और सेवा से इनकार करने वाले हमले शामिल हैं। 3. संपत्ति साइबर अपराधः यह प्रकार क्रेडिट कार्ड या यहां तक कि बौद्धिक संपदा अधिकार जैसी संपत्ति को लक्षित करता है। 4. समाज साइबर अपराधः यह साइबर अपराध का सबसे खतरनाक रूप है क्योंकि इसमें साइबर-आतंकवाद भी शामिल है। सबसे आम साइबर अपराध अब जब आप समझ गए हैं कि साइबर अपराध क्या हैं, तो आइए कुछ सामान्य साइबर अपराधों पर चर्चा करें। 1. फि शिंग और घोटालाः फि शिंग एक प्रकार का सोशल इंजीनियरिंग हमला है जो उपयोगकर्ता को लक्षित करता है और उपयोगकर्ता के बारे में संवेदनशील जानकारी प्राप्त करने के लिए नकली संदेश और ईमेल भेजकर या दुर्भावनापूर्ण सॉफ़्टवेयर डाउनलोड करने और लक्ष्य प्रणाली पर इसका फायदा उठाने की कोशिश करके उन्हें धोखा देता है। 2. पहचान की चोरी पहचान की चोरी तब होती है जब कोई साइबर अपराधी किसी अन्य व्यक्ति के व्यक्तिगत डेटा जैसे क्रेडिट कार्ड नंबर या व्यक्तिगत तस्वीरों का उपयोग धोखाधड़ी या अपराध करने के लिए उनकी अनुमति के बिना करता है। 3. रैनसमवेयर अटैक रैंसमवेयर हमले एक बहुत ही सामान्य प्रकार का साइबर अपराध है। यह एक प्रकार का मैलवेयर है जो उपयोगकताओं को एन्क्रिप्ट करके सिस्टम पर उनके सभी व्यक्तिगत डेटा तक पहुंचने से रोकने की क्षमता रखता है और फिर एन्क्रिप्टेड डेटा तक पहुंच देने के लिए फिरौती मांगता है। 4. कंप्यूटर नेटवर्क को हैक करना/दुरुपयोग करना यह शब्द निजी कंप्यूटर या नेटवर्क तक अनधिकृत पहुंच और इसे बंद करके या संग्रहीत डेटा या अन्य अवैध तरीकों से छेड़छाड़ करके इसका दुरुपयोग करने के अपराध को संदर्भित करता है। 5. इंटरनेट धोखाधड़ी इंटरनेट धोखाधड़ी एक प्रकार का साइबर अपराध है जिसमें इंटरनेट का उपयोग किया जाता है और इसे एक सामान्य शब्द माना जा सकता है जो इंटरनेट पर होने वाले सभी अपराधों जैसे स्पैम, बैंकिंग धोखाधड़ी, सेवा की चोरी आदि को समूहित करता है। साइबर क्राइम के अन्य प्रकार यहां अन्य 9 प्रकार के साइबर अपराध हैंः 1. साइबर बुलिंग इसे ऑनलाइन या इंटरनेट बुलिंग के नाम से भी जाना जाता है। इसमें किसी और के बारे में हानिकारक और अपमानजनक सामग्री भेजना या साझा करना शामिल है जो शर्मिंदगी का कारण बनता है और मनोवैज्ञानिक समस्याओं का कारण बन सकता है। यह हाल ही में बहुत आम हो गया है, खासकर किशोरों के बीच। 2. साइबर स्टॉकिंग साइबरस्टॉकिंग को अवांछित लगातार कॉल और संदेशों जैसे नियंत्रण और डराने के उद्देश्य से अन्य व्यक्तियों को ऑनलाइन लक्षित करने वाली अवांछित लगातार सामग्री के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। 3. सॉफ्टवेयर चोरी सॉफ़्टवेयर चोरी कॉपीराइट या लाइसेंस प्रतिबंधों के उल्लंघन के साथ भुगतान किए गए सॉफ़्टवेयर का अवैध उपयोग या प्रतिलिपि है। सॉफ़्टवेयर चोरी का एक उदाहरण तब होता है जब आप विंडोज की एक ताजा गैर-सक्रिय प्रतिलिपि डाउनलोड करते हैं और विंडोज सक्रियण के लिए वैध लाइसेंस प्राप्त करने के लिए ₹क्रैकर₹ के रूप में जाना जाता है। इसे सॉफ़्टवेयर चोरी माना जाता है. न केवल सॉफ्टवेयर को पायरेटेड किया जा सकता है बल्कि संगीत, फिल्में आदि को भी पायरेटेड किया जा सकता हैआर तस्वीरें. 4. सोशल मीडिया धोखाधड़ी किसी भी प्रकार की हानिकारक गतिविधियों को करने के लिए सोशल मीडिया फर्जी खातों का उपयोग करना जैसे अन्य उपयोगकताओं का रूप धारण करना या डराने या धमकी भरे संदेश भेजना। और सबसे आसान और सबसे आम सोशल मीडिया धोखाधड़ी में से एक है ईमेल स्पैम। 5. ऑनलाइन नशीली दवाओं की तस्करी क्रिप्टोक्यूरेंसी प्रौद्योगिकी के बड़े उदय के साथ, कानून प्रवर्तन का ध्यान आकर्षित किए बिना सुरक्षित निजी तरीके से धन हस्तांतरित करना और दवा सौदों को पूरा करना आसान हो गया। इससे इंटरनेट पर दवा विपणन में वृद्धि हुई। कोकीन, हेरोइन, या मारिजुआना जैसी अवैध दवाएं आमतौर पर ऑनलाइन बेची और कारोबार की जाती हैं, खासकर ₹डार्क वेब₹ के रूप में जानी जाने वाली साइट पर। 6. इलेक्ट्रॉनिक मनी लॉन्ड्रिंग इसे लेनदेन लॉन्ड्रिंग के रूप में भी जाना जाता है। यह अज्ञात कंपनियों या ऑनलाइन व्यवसाय पर आधारित है जो स्वीकार्य भुगतान विधियां और क्रेडिट कार्ड लेनदेन करता है लेकिन अज्ञात उत्पादों को खरीदने के लिए अधूरी या असंगत भुगतान जानकारी देता है। यह अब तक के सबसे आम और आसान मनी लॉन्ड्रिंग तरीकों में से एक है। 8. साइबर एक्सटॉर्शन साइबर एक्सटॉर्शन साइबर अपराधियों द्वारा चुराए गए कुछ महत्वपूर्ण डेटा को वापस देने या सेवा हमलों से इनकार करने जैसी दुर्भावनापूर्ण गतिविधियों को रोकने के लिए पैसे की मांग है। 9. बौद्धिक संपदा का उल्लंघन यह कॉपीराइट और औद्योगिक डिजाइन जैसे किसी भी संरक्षित बौद्धिक संपदा अधिकारों का उल्लंघन या उल्लंघन है। 9. ऑनलाइन भर्ती धोखाधड़ी कम आम साइबर अपराधों में से एक जो तेजी से लोकप्रिय हो रहा है, वह है आवेदकों से वित्तीय लाभ प्राप्त करने या यहां तक कि उनके व्यक्तिगत डेटा का उपयोग करने के उद्देश्य से फर्जी कंपनियों द्वारा जारी किए गए फर्जी नौकरी के अवसर। साइबर अपराध के उदाहरण - रेविल और कासिया रैनसमवेयर रेविल एक रूसी या रूसी भाषी हैकिंग समूह है और इसे रैंसमवेयर-ए-ए-सर्विस ऑपरेशन के रूप में जाना जाता है। कसेया घटना जुलाई-2021 में हुई थी. यह घटना तब हुई जब कासिया की कंपनी का एक उत्पाद कासिया के ग्राहक नेटवर्क के अंतिम बिंदुओं पर प्रसिद्ध रडउ्रठडङ्क्कफप्र्ऽ' रैंसमवेयर को तैनात कर रहा था, जिस पर दुनिया भर में कासिया के 1000 से अधिक ग्राहकों पर हमला किया गया था। कुछ घंटों बाद रेविल ने डार्क वेब पर अपनी हैप्पी ब्लॉग वेबसाइट पर पोस्ट करके हमले का श्रेय लिया और एक सार्वजनिक डिक्रिप्टर जारी करने के लिए 70 मिलियन डॉलर की फिरौती की मांग की, जिसके बारे में उनका दावा है कि यह सभी क्षतिग्रस्त डिवाइसों को डिक्रिप्ट कर सकता है। हमला इतना प्रभावशाली था कि संयुक्त राज्य सरकार ने रेविल सदस्यों को गिरफ्तार करने के लिए कोई भी जानकारी देने वाले को 10 मिलियन डॉलर का इनाम देने की पेशकश की। स्रोत 22 साल के यूक्रेनी यारोस्लाव वासिंस्की पर हमले का संचालन करने और कासिया और अन्य कंपनियों के खिलाफ रैंसमवेयर फैलाने का आरोप लगाया गया था। - स्टक्सनेट स्टक्सनेट घटना एक प्रसिद्ध घटना है जो 2010 में हुई थी। स्टक्सनेट एक कंप्यूटर वर्म (मैलवेयर का प्रकार) का नाम है जो रउअऊ्र (पर्यवेक्षी नियंत्रण और डेटा अधिग्रहण) सिस्टम को लक्षित करता है। स्टक्सनेट मैलवेयर ने ईरान के परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम को विनाशकारी क्षति पहुंचाई। यह यूएसबी ड्राइव के माध्यम से फैल रहा था और मुख्य रूप से माइक्रोसॉफ्ट विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम को प्रभावित करता था। मैलवेयर की कार्यक्षमता उन मशीनों की खोज करना थी जो पीएलसी (प्रोग्रामेबल लॉजिक कंट्रोलर) के रूप में काम कर रही हैं और यदि यह पाया गया तो मैलवेयर हमलावरों के माध्यम से इंटरनेट पर अपना कोड अपडेट कर देता है। - मैरियट होटल नवंबर 2018 में, मैरियट होटल समूह को बड़े पैमाने पर डेटा उल्लंघन का सामना करना पड़ा, जिससे 500 मिलियन से अधिक ग्राहक प्रभावित हुए। यह समझौता किसी अज्ञात पक्ष द्वारा अतिथि आरक्षण डेटाबेस के लिए हुआ। जो जानकारी थीलीक में ग्राहकों के लिए भुगतान जानकारी, मेलिंग पते, पासपोर्ट नंबर और फोन नंबर शामिल थे। मैरियट ग्रुप ने तुरंत सुरक्षा विशेषज्ञों के एक समूह के साथ घटना की जांच की और एक वेबसाइट और एक कॉल सेंटर स्थापित किया। उन्होंने प्रभावित ग्राहकों को ईमेल भी भेजे और उन्हें निगरानी उपकरणों तक मुफ्त पहुंच प्रदान की जो इंटरनेट पर नजर रखते हैं और व्यक्तिगत जानकारी साझा करने का कोई सबूत मिलने पर अलर्ट देते हैं। - रॉकयू डेटा ब्रीच रॉकयू एक कंपनी है जो खेल के क्षेत्र में काम करती है और इसकी स्थापना 2005 में लांस टोकुडा और जिया शेन द्वारा की गई थी। दिसंबर 2009 तक कंपनी अच्छा काम कर रही थी, जिसे ₹अब तक का सबसे बड़ा डेटा उल्लंघन₹ कहा जाता है। डेटा उल्लंघन ने रॉकयू डेटाबेस से 32 मिलियन से अधिक उपयोगकर्ता खाते की जानकारी को उजागर और लीक कर दिया। कंपनी पासवर्ड को अनएन्क्रिप्टेड प्लेन टेक्स्ट फॉर्मेट में स्टोर कर रही थी, जिससे हैकर के लिए स्टोर किए गए सभी पासवर्ड तक पहुंच आसान हो गई। हैकर ने डेटाबेस से सभी डेटा लीक करने के लिए एक बहुत पुरानी और लोकप्रिय रदछ भेद्यता का उपयोग किया। इस बड़े उल्लंघन के बाद, लीक हुए पासवर्डों का कुल सेट प्रवेश परीक्षण में एक बहुत ही सहायक संसाधन बन गया क्योंकि हैकर्स खातों और उत्पादों की सुरक्षा और पासवर्ड ताकत का परीक्षण करने के लिए पासवर्ड की इस वर्डलिस्ट का उपयोग करते हैं। आप इस आलेख में शीर्ष डेटा उल्लंघनों के बारे में अधिक पढ़ सकते हैं। साइबर अपराध को कैसे रोकें? खुद को और अपने पर्यावरण को साइबर अपराधों के जोखिम से बचाने के लिए कई सुझाव और दिशानिर्देश हैं जैसेः 1. सुनिश्चित करें कि आप एंटीवायरस और फायरवॉल जैसे नवीनतम सुरक्षा सॉफ़्टवेयर का उपयोग कर रहे हैं। 2. अपने परिवेश के लिए सर्वोत्तम संभव सुरक्षा सेटिंग्स और कार्यान्वयन लागू करें। 3. अविश्वसनीय वेबसाइटें ब्राउज न करें और अज्ञात फाइलें डाउनलोड करते समय सावधान रहें, और ईमेल अनुलग्नक देखते समय भी सावधान रहें। 4. मजबूत प्रमाणीकरण विधियों का उपयोग करें और अपने पासवर्ड को यथासंभव मजबूत रखें। आप इस लेख में अपने पासवर्ड को सुरक्षित रखने के टिप्स पा सकते हैं। 5. संवेदनशील जानकारी ऑनलाइन या अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर साझा न करें। 6. अपने बच्चों को इंटरनेट के उपयोग के जोखिमों के बारे में शिक्षित करें और उनकी गतिविधियों पर नजर रखें। 7. साइबर अपराध का शिकार होने पर पुलिस का हवाला देकर तत्काल प्रतिक्रिया देने के लिए हमेशा तैयार रहें।

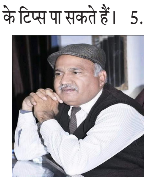

विजय गर्ग
मलोट पंजाब -152107

युवा शक्ति के प्रतीक एवं प्रेरणा-स्रोत आईपीएस मनुमुक्त 'मानव', जिन्हें एक दशक बाद भी भुला पाना संभव नहीं

नियति का यह कैसा दुखद विधान है कि विशिष्ट प्रतिभाओं को यहाँ अत्यल्प जीवन ही मिलता है। आदि शंकराचार्य से लेकर स्वामी विवेकानंद, स्वामी रामतीर्थ, श्रीनिवास रामानुजन, भारतेंदु हरिश्चंद्र और रांगेय राघव तक, एक लंबी सूची है ऐसे महापुरुषों की, जो अपनी चमक बिखेरकर अल्पायु में ही इस दुनिया से विदा हो गए। भारतीय पुलिस सेवा के युवा अधिकारी मनुमुक्त 'मानव' भी एक ऐसे ही प्रतिभा-पुंज थे, जिन्हें काल ने असमय ही अपना ग्रास बना लिया।

28 अगस्त, 2014 को बहुमुखी प्रतिभा के धनी, अत्यंत होनहार और प्रभावशाली पुलिस अधिकारी मनुमुक्त की 30 वर्ष, 9 माह की अल्पायु में नेशनल पुलिस अकेडमी, हैदराबाद (तेलंगाना) के स्विमिंग पूल में डूबने से, संदिग्ध परिस्थितियों में, मृत्यु हो गई थी। स्विमिंग पूल के पास ही स्थित ऑफिसर्स क्लब में चल रही विदाई पार्टी के बाद, आधी रात को जब मनुमुक्त का शव स्विमिंग पूल में मिला, तो अकेडमी में ही नहीं, पूरे देश में हड़कंप मच गया, क्योंकि यह अकेडमी के 66 वर्ष के इतिहास में घटित होने वाली पहली इतनी बड़ी दुर्घटना थी। यहीं यह बताना भी आवश्यक है कि इतनी मर्मांतक और दुर्भाग्यपूर्ण त्रासदी के बाद भी इस मामले की न तो ठीक-से जांच हुई और न ही किसी अधिकारी या कर्मचारी की जिम्मेदारी तय कर, उसके विरुद्ध दंडात्मक कार्यवाही की गई। मनुमुक्त के पिता डॉ. रामनिवास 'मानव' भरे मन से बताते हैं कि अधिकारियों की आपराधिक लापरवाही और मनुमुक्त की मृत्यु के षड्यंत्र में शामिल उनके बैचमेट अफसरों की संलिप्तता के दस्तावेजी सबूतों के बावजूद, उनके विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं हुई, बल्कि तेलंगाना पुलिस और सीबीआई ने इसे सामान्य घटना बताकर मामले को रफा-दफा कर दिया। तेलंगाना पुलिस और सीबीआई का पूरा प्रयास दोषियों को बचाने का था, दोषियों को सजा दिलाने का नहीं। यही नहीं, मनुमुक्त को ट्रेनी बताकर सभी सरकारों ने पल्ला झाड़ लिया, किसी ने एक रुपये की भी आर्थिक सहायता परिवार को प्रदान नहीं की।

उल्लेखनीय है कि मनुमुक्त 2012 बैच और हिमाचल प्रदेश काडर के परम मेधावी और ऊर्जावान पुलिस अधिकारी थे। 23 नवंबर, 1983 को हिसार (हरियाणा) में जन्मे तथा पंजाब विश्वविद्यालय, चंडीगढ़ से उच्च शिक्षा प्राप्त मनुमुक्त ने 'सी' सर्टिफिकेट सहित एनसीसी की सभी सर्वोच्च उपलब्धियाँ प्राप्त की थीं। वह बहुत अच्छे चिंतक होने के साथ-साथ बहुमुखी कलाकार और सफल फोटोग्राफर भी थे; सेल्फी के तो मास्टर ही थे। उनकी समाज-सेवा में भी बड़ी रुचि थी। वह अपने दादा-दादी की स्मृति में अपने पैतृक गाँव में स्वास्थ्य-केंद्र तथा नारनौल में सिविल सर्विस एकेडमी स्थापित करना चाहते थे। देश और समाज के लिए उनके और भी बहुत सारे सपने थे, जो उनकी असामयिक मृत्यु के साथ ही ध्वस्त हो गए।

मनुमुक्त के पिता डॉ. रामनिवास 'मानव' भरे मन से बताते हैं कि अधिकारियों की आपराधिक लापरवाही और मनुमुक्त की मृत्यु के षड्यंत्र में शामिल उनके बैचमेट अफसरों की संलिप्तता के दस्तावेजी सबूतों के बावजूद, उनके विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं हुई, बल्कि तेलंगाना पुलिस और सीबीआई ने इसे सामान्य घटना बताकर मामले को रफा-दफा कर दिया। तेलंगाना पुलिस और सीबीआई का पूरा प्रयास दोषियों को बचाने का था, दोषियों को सजा दिलाने का नहीं। यही नहीं, मनुमुक्त को ट्रेनी बताकर सभी सरकारों ने पल्ला झाड़ लिया, किसी ने एक रुपये की भी आर्थिक सहायता परिवार को प्रदान नहीं की।

इकलौते जवान आईपीएस बेटे की मृत्यु मनुमुक्त के पिता, वरिष्ठ साहित्यकार और शिक्षाविद् डॉ. रामनिवास 'मानव' तथा माता अर्थशास्त्र की पूर्व प्राध्यापिका डॉ. कांता भारती के लिए भयानक वज्रपात से कम नहीं थी। कोई अन्य दम्पत्ति होता, तो शायद टूटकर बिखर जाता, लेकिन 'मानव' दम्पत्ति ने अद्भुत धैर्य और साहस का परिचय देते हुए, न केवल इस अकल्पनीय-असहनीय पीड़ा को झेला, बल्कि अपने बेटे की स्मृतियों को सहेजने और सजीव बनाए रखने के लिए भरसक प्रयास भी प्रारंभ कर दिए। उन्होंने अपनी संपूर्ण जमापूंजी लगाकर 10 अक्टूबर, 2014 को मनुमुक्त 'मानव' मेमोरियल ट्रस्ट का गठन किया और नारनौल में 'मनुमुक्त भवन' का निर्माण कर उसमें वातानुकूलित लघु सभागार, संग्रहालय और पुस्तकालय की स्थापना की। ट्रस्ट द्वारा अढाई लाख का एक अंतरराष्ट्रीय पुरस्कार, एक लाख का एक राष्ट्रीय पुरस्कार, 21-21 हजार के दो तथा 11-11 हजार के तीन राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय पुरस्कार और सौ मनुमुक्त 'मानव' स्मृति-सम्मान प्रारंभ किए। दोनों बड़े पुरस्कार फिलहाल स्थगित हैं, किंतु शेष सभी पुरस्कार-सम्मान प्रतिवर्ष, नियमित रूप से, प्रदान किए जा रहे हैं। 'मनुमुक्त भवन' में राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय स्तर के साहित्यिक-सांस्कृतिक कार्यक्रम भी निरंतर चलते रहते हैं, जिनमें अब तक भारत के अतिरिक्त जापान, फीजी, आस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, थाईलैंड, सिंगापुर, इंडोनेशिया, नेपाल, श्रीलंका, ब्रिटेन, नीदरलैंड, जर्मनी, फ्रांस, नॉर्वे, तुर्की, रूस, मॉरिशस, कोस्टारिका, अमेरिका, कनाडा आदि दो दर्जन देशों की लगभग पांच सौ विशिष्ट विभूतियाँ सहभागिता कर चुकी हैं। ट्रस्ट द्वारा ऑन लाइन आयोजित कार्यक्रमों में तो 55-60 देशों के विभिन्न क्षेत्रों के प्रमुख साहित्यकार, पत्रकार, फिल्मकार, शिक्षाविद्, समाजसेवी, पर्यावरणविद्, खिलाड़ी, पर्वतारोही, प्रशासनिक अधिकारी और राजनेता जुड़ चुके हैं तथा यह सिलसिला अब भी जारी है। मात्र सात वर्ष की अल्पावधि में ही, अपनी उपलब्धियों के कारण, नारनौल का 'मनुमुक्त भवन' अंतरराष्ट्रीय सांस्कृतिक केंद्र के रूप में प्रतिष्ठित हो चुका है। ट्रस्ट द्वारा 15 अगस्त, 2021 में, भारत की स्वतंत्रता के अमृत-महोत्सव के अवसर पर आयोजित 'वर्चुअल अंतरराष्ट्रीय कवि-सम्मेलन' को, विश्व के सर्वाधिक देशों के सबसे बड़े कवि-सम्मेलन के रूप में 'गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड' में दर्ज किया जा चुका है। छह महाद्वीपों और इक्यावन देशों के पिचहत्तर कवियों ने इस कवि-सम्मेलन में एक साथ काव्य-पाठ कर यह विश्व-रिकॉर्ड बनाया था।

मनुमुक्त 'मानव' युवा शक्ति के प्रतीक ही नहीं, प्रेरणा-स्रोत भी थे। देहांत के एक दशक बाद भी उन्हें बड़े सम्मान के साथ स्मरण किया जाता है। परिवार ने मीडिया, सोशल मीडिया और फेसबुक के माध्यम से उनकी प्रेरक स्मृतियों को जीवित रखा हुआ है। इसके लिए मनुमुक्त की बड़ी बहन और विश्वबैंक, वाशिंगटन डीसी (अमरीका) की वरिष्ठ अर्थशास्त्री डॉ. एस अनुकृति का भी भरपूर सहयोग रहता है। अंत में मनुमुक्त की बैचमेट, भारतीय प्रशासनिक सेवा की अधिकारी और संप्रति धमतरी (छत्तीसगढ़) की जिलाधिकारी नम्रता गांधी के शब्दों में इतना ही कहा जा सकता है, ₹मनुमुक्त हमारे लिए बड़े भाई, मित्र, दार्शनिक और मार्गदर्शक थे। उनके व्यक्तित्व में उत्तम हास्य का समावेश था, वहीं उनका दिल भी विशुद्ध सोने का बना था। उनके अंतर्मन में बड़ी गहराई थी, जिसका बाहर से अनुमान लगाना कठिन था। वह शानदार प्रशासक, स्वाभाविक नेता, श्रेष्ठ टीम-खिलाड़ी, सम्मानित वरिष्ठ, विश्वसनीय कनिष्ठ और सबके चहेते साथी तथा सहयोगी थे। हममें से किसी के लिए भी उन्हें भुला पाना संभव नहीं है।

प्रियंका सौरभ

अदालतों के निर्देश भी नहीं सुधार सके नदियों की सेहत

हिन्दू शास्त्रों में गंगा और यमुना नदी का धार्मिक महत्व बताया गया है। इन नदियों की उपयोगिता के कारण इन्हें जीवनदायिनी कहा गया है। वर्तमान में हालत यह है कि ये जीवनदायिनी खुद जीवन के लिए तरस रही हैं। देश में अन्य समस्याओं की तरह इन नदियों के की बबार्दी के लिए भी राजनीति जिम्मेदार है। नदियों का प्रदूषण का मुद्दा राजनीतिक दलों को वोट नहीं दिला सकता, इसलिए इनकी सेहत लगातार बिगड़ती जा रही है। सत्तारुढ़ दलों की प्राथमिकता में नदियों की पवित्रता बरकरार रखना नहीं रह गया है। इन नदियों की हालत नालों जैसी बन चुकी है। भ्रष्टाचार और वोट बैंक की राजनीति के कारण इस हालत से निपटने के लिए सरकारी प्रयास विफल साबित हुए हैं। राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण, हाईकोट और सुप्रीम कोर्ट के दखल के बावजूद नदियों में अपेक्षित सुधार नहीं हो पा रहा है। अदालतों ने नदियों में प्रदूषण के लिए कई बार भारी जुमार्ना लगाया है। चुंकि जुमार्ना नेता-अफसरों की जेब से नहीं जाता, इसलिए उसका ऊंट के मुंह में जीरे जितना ही असर हुआ है।

सुप्रीम कोर्ट ने यमुना नदी को अनुपचारित अवशिष्ट से प्रदूषित करने के लिए आगरा नगर निगम को 58.39 करोड़ रुपये पर्यावरणीय मुआवजा देने का आदेश दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने नगर निगम के सारे दावों की पोल खोल कर रख दी और यमुना नदी में बढ़ते प्रदूषण स्तर को लेकर नगर निगम को फटकार लगाई। इस तरह के मामले में इससे राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण (एनजीटी) ने भी नगर निगम के खिलाफ अप्रैल में आदेश दिया था। यह पहला मौका नहीं है कि जब एनजीटी या अदालत ने नदियों के प्रदूषण के लिए सरकारी एजेंसियों पर जुमार्ना लगाया हो, इससे पहले भी ऐसे कदम उठाए जा चुके हैं, किन्तु शासन-प्रशासन की मिलीभगत से नदियों में प्रदूषण का स्तर का बढ़ता जा रहा है। हालात यह हो गए हैं कि नदियों का जल पीने लायक तो दूर आचमन करने लायक भी नहीं रह गया है।

दिल्ली में बहने वाली यमुना नदी कभी धार्मिक और सांस्कृतिक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण थी। अब प्रदूषण के कहर से जूझ रही है। आंकड़े बताते हैं कि यमुना का प्रदूषण स्तर खतरनाक स्तर तक पहुंच चुका है। छठ जैसे पर्व पर महिलाओं को इस नदी पर स्नान करने से रोक लगाई गई। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के आंकड़ों के अनुसार, यमुना में खतरनाक बैक्टीरिया और प्रदूषकों का स्तर मानक सीमा से कई गुना अधिक पाया गया है। दिल्ली में यमुना के प्रमुख हिस्सों में पानी की गुणवत्ता, बीओडी (बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड) और अन्य प्रदूषक तत्वों के कारण न केवल पीने के योग्य नहीं है। यमुना में प्रतिदिन लगभग 3,000 मिलियन गैलन से अधिक सीवेज प्रवाहित होता है। यह बिना किसी सफाई प्रक्रिया के सीधे नदी में जा रहा है।

राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण ने नोएडा विकास प्राधिकरण पर 100 करोड़ यानी एक अरब रुपये और दिल्ली जल बोर्ड पर 50 करोड़ रुपये का जुमार्ना लगाया थ। इसी तरह बिहार सरकार में नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) ने सॉलिड और लिक्विड वेस्ट का वैज्ञानिक तरीके से निपटारा नहीं कर पाने को लेकर राज्य सरकार पर चार हजार करोड़ रुपये का जुमार्ना लगाया। सर्वोच्च न्यायालय ने 28 नवंबर, 2023 को एनजीटी के उस आदेश पर रोक लगा दी, जिसमें महाराष्ट्र को अनुचित अपशिष्ट प्रबंधन के लिए पर्यावरण मुआवजे के रूप में 12,000 करोड़ रुपये का भुगतान करने का निर्देश दिया गया था। एनजीटी ने पंजाब सरकार पर कई चेतावनियों के बावजूद राज्य में ठोस और तरल अपशिष्ट प्रबंधन में विफल रहने के लिए 1,000 करोड़ रुपये का जुमार्ना लगाया। इसी तरह सुप्रीम कोर्ट ने नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल द्वारा राजस्थान सरकार पर लगाए 3000 करोड़ रुपये के जुमार्ने पर रोक लगा दी। एनजीटी ने राजस्थान में गीले और सूखे कचरे के समुचित प्रबंधन में नाकाम रहने से पर्यावरण पर पड़ रहे बुरे असर को लेकर यह जुमार्ना लगाया था। सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरमेंट (सीएसई) की ओर से 5 जून को पर्यावरण दिवस के मौके पर जारी स्टेट ऑफ एनवायरमेंट (एसओई) रिपोर्ट 2023 में यह खुलासा किया कि देश के 30 राज्यों में कुल 279 (46 फीसदी) नदियां प्रदूषित हैं, हालांकि, 2018 के मुकाबले मामूली सुधार 2022 में देखा गया है। 2018 में 31 राज्यों में 323 नदियां प्रदूषित थीं। एसओई रिपोर्ट के मुताबिक देश की 279 अथवा 46 फीसदी प्रदूषित नदियों में सर्वाधिक प्रदूषित नदियां महाराष्ट्र (55) में हैं जबकि इसके बाद मध्य प्रदेश में 19 नदियां प्रदूषित हैं वहीं, बिहार में 18 और केरल में18 नदियां प्रदूषित हैं। उत्तर प्रदेश में 17 और कर्नाटक में 17 नदियां जबकि राजस्थान में 14 और गुजरात में 13, मणिपुर में 13, पश्चिम बंगाल में 13 नदियां प्रदूषित हैं। देश की सर्वाधिक पवित्र नदी गंगा के जल को घरों में रखा जाता था।

अब हालत यह है कि गंगा नदी दो साल में 10 गुना मैली चुकी है। उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल के 94 जगहों से गंगा जल की जांच की गई। नदी के पानी में प्रदुषण का बुरा हाल देखने को मिला। प्लास्टिक की थैलियों, दूध की पॉलीथीन, नदी के किनारे शवों का जलाना, गंगा नदी को लगातार प्रदूषित कर रहा है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल के 94 स्थानों पर गंगा जल की जांच में यह भयावह तस्वीर सामने आई थी। 13 फरवरी 2023 को केंद्रीय जल शक्ति (जल संसाधन) राज्य मंत्री विश्वेश्वर टुडू ने संसद को बताया था कि नमामि गंगे कार्यक्रम गंगा नदी में प्रदूषण को कम करने में कारगर रही है। उन्होंने कहा था कि 2014 से केंद्र ने नदी की सफाई के लिए 32,912.40 करोड़ रुपये के बजट के साथ 409 परियोजनाएं शुरू की हैं। लेकिन केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के मुताबिक गंगा नदी के पूरे भाग के 71 प्रतिशत क्षेत्र में कोलीफॉर्म के खतरनाक स्तर पाए गए। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की 2022 की रिपोर्ट में बताया गया कि उत्तर प्रदेश में कोलीफॉर्म का स्तर सात स्टेशनों पर सबसे ज्यादा था। एनजीटी ने राज्यों से सीवेज ट्रिटमेंट पर रिपोर्ट दाखिल करने को कहा था। इसी की पालना में दिसंबर 2022 में उत्तर प्रदेश ने अपनी रिपोर्ट पेश की, जिसमें स्वीकार किया गया कि गंगा और उसकी सहायक नदियों में मिलने वाले 1,340 नालों में से 895 (66.8 प्रतिशत) बिना किसी सिवेज ट्रिटमेंट के सीधा गंगा को दुषित कर रहे हैं। वर्तमान में भी हालात में ज्यादा सुधार नहीं है। वर्ष 2018-2019 में गंगा द्वारा ले जाए गए प्लास्टिक कचरे की का आकलन किया गया। नेशनल जियोग्राफिक सोसाइटी के गंगा नदी अभियान में ये पाया गया कि गंगा नदी का प्लास्टिक का कचरा बड़े पैमाने पर सुमद्र में मिल रहा है।

एक नए अध्ययन से पता चला है कि दुनिया के कुल प्लास्टिक कचरे का लगभग 20 प्रतिशत भारत में पैदा होता है।

यूनिवर्सिटी ऑफ लीड्स की एक हालिया रिपोर्ट में कहा गया है कि हर साल देश में लगभग 9.3 मिलियन टन प्लास्टिक कचरा पैदा होता है, जिसमें से 90 प्रतिशत नगर निगमों से आता है। नेचर में प्रकाशित रिपोर्ट में वैश्विक स्तर पर 50,000 से अधिक नगर पालिकाओं में प्लास्टिक कचरे पर नजर रखने के लिए उन्नत एआई मॉडल का इस्तेमाल किया गया।

प्रकृति का सबसे बड़ा खजाना नदियों को शुद्ध रखने के प्रयासों की कमजोर हालत के कारण वे दिन दूर नहीं जब देश में जल संकट और गहरा होगा। शासन-प्रशासन और अदालतों ने शीघ्र इस दिशा में ध्यान नहीं दिया तो कृषि के लिए तो दूर पीने के पानी के लिए भी तरसना पड़ेगा।

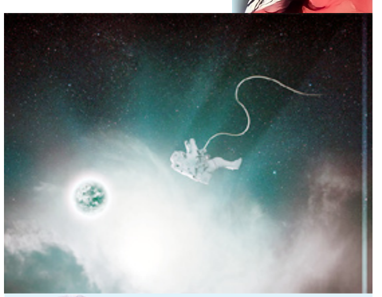

स्वप्न

बादलों की ओट में
खिला छुपा चाँद
पहाड़ों पर जाती पगडण्डी
मन आकाश में
चाँद के इंतजार में
घुप्प अंधेरा रात स्याही
विरहन सी
पत्तो की सरसराहट
उल्लू की कराहती आवाजे
लगता मृत्यु जीवन को गले लगाए बैठी।
चाँद निकला बादलों से
सूखे दरख्तो सूखी नदियों ने
ओढ रखा हो धवल चाँदनी का कफन
जंगल कम ,नदियाँ प्रदूषित हो सूखी
मानों ऐसा लगता
मोत हो चुकी पर्यावरण की
धरा से आँखे चुराता चाँद
छूप जाता बादलों की ओट।
निंद्रा टूटी स्वप्न छूटा
भोर हुई
नई उम्मीदों से जंगल सजाने
नदियों की कलकल
चिड़ियों की चचहाहट ने दिया
पर्यावरण को पुनर्जन्म।

संजय वर्मा 'दृष्टि'
मनावर जिला धार (म प्र)

लोकसेवा आयोग की परीक्षाएं व अभ्यर्थियों का प्रदर्शन

सरकार इन अभ्यर्थियों के खिलाफ पुलिस की लाठी का प्रयोग करके समझाना चाहती है। यही कारण है कि पुलिस के लाठीचार्ज के बाद भगदड़ से बहुत से छात्र चोटिल हो गए है। प्रयागराज में आयोग के कार्यालय पर धरना देने के लिए कई हजार छात्र जुटे हुए हैं जिनमें उत्तर प्रदेश के ही नहीं, बिहार, मध्यप्रदेश, उत्तराखंड और दिल्ली आदि प्रदेशों के अभ्यर्थी भी है।

जिस प्रकार देश और प्रदेश में आबादी और पढ़े लिखे लोगों की संख्या बढ़ रही है उसके कारण प्रतियोगी परीक्षाओं में बड़ी संख्या में अभ्यर्थियों की भागीदारी होना भी स्वाभाविक ही है। यही कारण है कि पहले जो परीक्षाएं मुख्य परीक्षा और साक्षात्कार के माध्यम से ही निस्तारित हो जाती थी अब उनमें प्री' यानी प्रारम्भिक परीक्षा भी करायी जाने लगी है। जिसके कारण जो अभ्यर्थी प्री में ही घंट जाते हैं। वे मुख्य परीक्षा तक नहीं पहुंचते और मुख्य परीक्षा के बाद सत्कार होने से बनी मेरिट ही तय करती है कि कौन क्वालिफाई हुआ है और किसे नियुक्ति मिल सकेगी। यह परीक्षाएं न्यूनतम योग्यता या पासिंग मार्क्स पर निर्भर नहीं करती है बल्कि इनकी मेरिट ही इन्हें तय करती है कि कौन आगे जा पायेगा और कौन वहीं ठहर जायेगा। यही कारण है कि प्रतियोगी परीक्षाओं के छात्र-छात्राएं आंदोलित है। क्योंकि यह उनके भविष्य से जुड़ा प्रश्न है। किसी भी प्रश्नपत्र के कई सेट तैयार किए जाते हैं जिनके अंक भी समान होते हैं लेकिन जब परीक्षाएं दूसरे दिन होगी या दूसरी पाली में भी वहीं परीक्षा होगी तो उसके प्रश्नपत्र बदल जायेंगे जिसका प्रभाव अभ्यर्थियों को मिलने वाले अंकों पर पड़ेगा। अब सरकार दो दिन परीक्षाएं कराकर आयोग अभ्यर्थियों को नार्मलाइजेशन का पाठ पढ़ा रहा है। दो दिन परीक्षाएं होने का मतलब ही यही है कि प्रश्नपत्र समान नहीं होंगे। पहले दिन जो अभ्यर्थी परीक्षा देगा उस दिन हो सकता है कि प्रश्नपत्र सरल है और दूसरे दिन जो दूसरे अभ्यर्थी परीक्षा दें उनका प्रश्नपत्र कठिन हो। ऐसे में नार्मलइजेशन कराकर आयोग अभ्यर्थियों को यह बता रहा है कि कठिन प्रश्नों के आधार पर मिले अभ्यर्थियों को नम्बर के आधार पर मानकीकरण किया जायेगा। जिसमें कोई पारदर्शिता हो ही नहीं सकती है। यही कारण है कि छात्र आंदोलित है। क्योंकि किसी भी परीक्षा की तैयारी एक दिन में नहीं हो जाती है इसके लिए अभ्यर्थियों को कई साल और महीने रुपए-पैसे और समय खर्च होता है तब कही जाकर परीक्षा को लोग क्वालिफाई कर पाते है। सरकार जैसा की हमेशा करती आयी है अपने ही मुद्दे पर अड़ी हुई है। वह तरह-तरह के तर्क दे रही है। वह नीट और अन्य परीक्षाओं के उदाहरण दे रही है। वहीं सरकार के एक उपमुख्यमंत्री छात्रों के बीच पहुंचकर उनकी समस्या का निवारण करने के लिए नहीं विपक्ष कहीं इस आंदोलन को न उठा ले इसके लिए समर्थन कर रहे हैं। कोई उपमुख्यमंत्री इस स्थिति में तो है कि वह अपनी ही सरकार तक इस समस्या को हल कर रास्ता निकाले नही सिर्फ वार्ता करे। प्रदेश में पेपर लीक और अन्य कारणों से सरकार पुलिस भर्ती की भांति ही अब पीसीएस प्री और आरओ की परीक्षाओं के सेंटर कम करके उसे दो दिनों में कराने का निर्णय किया है। जिस नीट का हवाला सरकार दे रही है उसमें भी घालमेल और पेपरलीक हो चुका है। जिसके तार एक प्रदेश से होते हुए कई प्रदेशों में फैले हुए पाये गए।

सरकार ने परीक्षा सेंटर घटा दिये है। लेकिन इसमें छात्रों का क्या दोष? सरकार अपनी व्यवस्था करने में सक्षम नहीं हो पा रही है इसलिए वह चाहती है कि जो वह तय कर दे वहीं अन्तिम है। क्योंकि उसके पास राजनीतिक बहुमत है इसलिए वह कुछ भी तय कर सकती है। आयोग तो उसके हाथ की कठपुतली है। आयोग का अध्यक्ष कौन होगा यह तो सरकार ही तय करती है। सरकार को यह समझना चाहिए कि पुलिस बल उतार कर सारी समस्याओं का हल नहीं निकाला जा सकता है। इसके लिए पारदर्शिता की नीति अपनायी जानी थी। यदि सरकार ऐसा करना चाहती थी तो पहले उसे अधिसूचना के समय ही इस बात की जानकारी दे देनी चाहिए कि वह दो दिनों में परीक्षाएं करायेगी ऐन परीक्षा के समय नये नियम लाद दिए जायें इसे कैसे उचित ठहराया जा सकता है। इसलिए सरकार को इस मामले पर पुनर्विचार करना चाहिए और आयोग की मनमानापन करने के बजाय पारदर्शिता अपनानी चाहिए।

उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा प्रांतीय सिविल सेवा (पीसीएस) प्री यानी प्रारम्भिक और समीक्षा अधिकारी (आरओ) सहायक समीक्षा अधिकारी (एआरओ) की परीक्षा दो दिन कराने के निर्णय के विरोध में प्रतियोगी परीक्षा के अभ्यर्थी उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के कार्यालय के सामने दो दिनों से निरन्तर धरना दे रहे हैं और थाली कटोरी चम्मच लेकर सरकार और उसके आयोग को जगाने की कोशिश कर रहे हैं।

इस दौरान इन प्रतियोगी छात्र-छात्राओं को पुलिस से कई दौर की झड़प हो चुकी है और इन अभ्यर्थियों को खदेड़ने के लिए पुलिस ने इन पर लाठीचार्ज भी किया है। जिससे इनका आक्रोश और बढ़ गया है और उन्होंने अब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के चुनावी नारे 'बटेंगे तो कटेंगे' की तर्ज पर न्याय मिले बिना नहीं हटेंगे' 'बटें नहीं हटेंगे नहीं' का नारा दिया है। आयोग ने पीसीएस प्री की परीक्षा सात और आठ दिसंबर और समीक्षा अधिकारी व सहायक समीक्षा अधिकारी (आरओ एवं एआरओ) की परीक्षा 22-23 दिसंबर कराना तय किया है। जबकि आयोग ने अपनी अधिसूचना में इस बात का कहीं भी उल्लेख नहीं किया था कि यह परीक्षाएं दो दिनों में करायी जायेंगी। कई माह जीतने के बाद जब आयोग की परीक्षा कराने की याद आयी तो अभ्यर्थियों की संख्या को देखते हुए सरकार के हाथ-पांव फूल गए और परीक्षा दो दिनों में कराने का निर्णय कर दिया। पहले की अपेक्षा सेंटर कम कर दिये। जिसके कारण अभ्यर्थी आक्रोशित है। आयोग द्वारा तारीख घोषित किए जाने के बाद ही छात्रों ने 11 नवम्बर से उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग दफ्तर के समाने धरना प्रदर्शन करने की चेतावनी दे दी थी। सरकार ने इसके पहले आर ओ और एआरओ की परीक्षा फरवरी में करायी थी जो पेपरलीक होने और अन्य अनियमितताओं के कारण निरस्त कर दी गई थी। पिछले छःसात वर्षों में जितनी भी प्रतियोगी या नौकरियों के लिए परीक्षाएं हुई अधिकांश के पेपरलीक हुए या अनियमितता की शिकार हुई। यहां तक कि पुलिस भर्ती परीक्षा भी दोबारा आयोजित कराये गई जो कई पालियों और कई दिनों में करायी गई। लेकिन सरकार इसका समाधान करने के बजाय अपने द्वारा तय कर दी गई प्रक्रिया पर अड़ी हुई है और वह तरह-तरह के विभिन्न परीक्षाओं के तर्क दे रही है। सरकार इन अभ्यर्थियों के खिलाफ पुलिस की लाठी का प्रयोग करके समझाना चाहती है। यही कारण है कि पुलिस के लाठीचार्ज के बाद भगदड़ से बहुत से छात्र चोटिल हो गए है। प्रयागराज में आयोग के कार्यालय पर धरना देने के लिए कई हजार छात्र जुटे हुए हैं जिनमें उत्तर प्रदेश के ही नहीं, बिहार, मध्यप्रदेश, उत्तराखंड और दिल्ली आदि प्रदेशों के अभ्यर्थी भी है।

सरकार ने परीक्षा सेंटर घटा दिये है। लेकिन इसमें छात्रों का क्या दोष? सरकार अपनी व्यवस्था करने में सक्षम नहीं हो पा रही है इसलिए वह चाहती है कि जो वह तय कर दे वहीं अन्तिम है। क्योंकि उसके पास राजनीतिक बहुमत है इसलिए वह कुछ भी तय कर सकती है। आयोग तो उसके हाथ की कठपुतली है। आयोग का अध्यक्ष कौन होगा यह तो सरकार ही तय करती है। सरकार को यह समझना चाहिए कि पुलिस बल उतार कर सारी समस्याओं का हल नहीं निकाला जा सकता है। इसके लिए पारदर्शिता की नीति अपनायी जानी थी। यदि सरकार ऐसा करना चाहती थी तो पहले उसे अधिसूचना के समय ही इस बात की जानकारी दे देनी चाहिए कि वह दो दिनों में परीक्षाएं करायेगी ऐन परीक्षा के समय नये नियम लाद दिए जायें इसे कैसे उचित ठहराया जा सकता है। इसलिए सरकार को इस मामले पर पुनर्विचार करना चाहिए और आयोग की मनमानापन करने के बजाय पारदर्शिता अपनानी चाहिए।

अभी हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा है कि सरकारी नौकरियों में भर्ती नियमों के चीच प्रक्रिया में नहीं बदल सकते पानी विज्ञापन के बाद नियम नहीं जोड़ी जा सकती है। तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश डी. वाई. चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पांच न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने कहा कि. भर्ती प्रक्रिया शुरू होने से पहले निर्धारित किए जा चुके नियमों से बीच में छेड़छाड़ नहीं की जा सकती। चयन नियम मनमाने नहीं बल्कि संविधान के अनुच्छेद 14 के अनुरूप होने चाहिए। बीच में नियमों में बदलाव करके उम्मीदवारों को हैरान-परेशान नहीं किया जाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला तेज प्रकाश पाठक बनाम राजस्थान उच्च न्यायालय मामले में सुनाया था लेकिन यहां तो स्थिति यह है कि खेल के पहले नियम घोषित करने के बजाय खेल के समय नियम घोषित किए जा रहे हैं। इसके माध्यम से क्या सरकार यह चाहती है कि यह अभ्यर्थी अदालत जायें और अदालती आदेशों में लगने वाले समय और पैसे के बीच झूलते रहें इससे आयोग भी बच जाये और सरकार को भी मशकत न करना पड़े। 'हर लगे न फिटकरी रंग चोखा अपने आप ही हो जाये।

अभी हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा है कि सरकारी नौकरियों में भर्ती नियमों के चीच प्रक्रिया में नहीं बदल सकते पानी विज्ञापन के बाद नियम नहीं जोड़ी जा सकती है। तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश डी. वाई. चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पांच न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने कहा कि. भर्ती प्रक्रिया शुरू होने से पहले निर्धारित किए जा चुके नियमों से बीच में छेड़छाड़ नहीं की जा सकती। चयन नियम मनमाने नहीं बल्कि संविधान के अनुच्छेद 14 के अनुरूप होने चाहिए। बीच में नियमों में बदलाव करके उम्मीदवारों को हैरान-परेशान नहीं किया जाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला तेज प्रकाश पाठक बनाम राजस्थान उच्च न्यायालय मामले में सुनाया था लेकिन यहां तो स्थिति यह है कि खेल के पहले नियम घोषित करने के बजाय खेल के समय नियम घोषित किए जा रहे हैं।

देश में नौकरियों का बुरा हाल है। न समय से परीक्षाएं हो पाती है न ही परिणाम आ पाते हैं। परीक्षा के समय से ही अदालत में मामले झूलने लगते हैं। यदि किसी के परिणाम कई साल बाद आ भी गए तो उसके बाद भी मामले अदालतों में चले जाते है और मामला जहां का तहां ही रह जाता है। लोग तैयारी करते करते अपनी उम्र की अहंता गवां बैठते हैं। जहां तक उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की शुचिता और पारदर्शिता का प्रश्न है। पीसीएस जे की कापियों के बदलने की स्थिति से इसका अन्दाजा लगाया जा सकता है कि हो क्या रहा है? यह लोक सेवा आयोग लगभग एक दशक से अधिक समय से विवादों में घिरा रहा है।

चुनावी वादे जनता की भलाई के लिए हैं या फिर ...

मुफत ... मुफ्त चुनाव आते ही किसी क्लियरेंस सेल जैसा माहौल तैयार हो जाता है। रास्ते का माल सस्ते में की तर्ज पर राजनीतिक पार्टियां वादे पर वादा करती जाती हैं और अब तो ज्यादातर पार्टियां सरकार बनते ही उन वादों को पूरा करने में भी जुट जाती हैं। कई दशक पहले दक्षिणी राज्यों से शुरु हुआ यह सिलसिला अब करीब-करीब पूरे देश में विस्तारित हो चुका है। आश्चर्यजनक बात यह है कि हरेक पार्टी ऐसे वादे करती है और दूसरे पर उंगली उठाने का मौका नहीं छोड़ती। हाल ही में झारखंड और महाराष्ट्र में चुनाव गर्मी पकड़ ही रहा था कि एक बार फिर यह किस्सा खुल गया। मजेदार बात यह है कि इस बार वाद-विवाद की शुरुआत कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे के एक बयान से हुई और वह भी कांग्रेस की सरकार वाले राज्य कर्नाटक में। खरगे ने बयान को प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने लपक लिया और फिर कांग्रेस के नेता भी खुलकर मैदान में आ गए। शुरुआत इस बात से हुई कि कर्नाटक सरकार महिलाओं के लिए मुफ्त बस सेवा देने वाली शक्ति योजना खत्म करने जा रही है। खरगे के सवाल उठाते ही कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरामैया और उप-मुख्यमंत्री डी के शिवकुमार ने तुरन्त उन्हें दुरुस्त किया और कहा कि योजना की समीक्षा की बात हुई है, खत्म करने की नहीं। लेकिन यह बात खुले मंच से हुई, जहां पूरे प्रदेश का मीडिया उपस्थित था। खरगे ने एक तरह से राज्य के नेताओं को फटकार लगाते हुए कहा कि उन्हें ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए, जिनका दूसरी पार्टियां फायदा उठा सकें। साथ ही उन्होंने यह भी कह दिया कि राज्य का बजट देखकर ही गारंटी देनी चाहिए। अगर आप बजट से ज्यादा की गारंटी दे देंगे, तो दिवालिया हो जाएंगे। सड़क बनाने के लिए मिट्टी तक नहीं मिलेगी। और लोग आपको दोष देंगे। उनका यह बयान झारखंड व महाराष्ट्र विधानसभा चुनावों के लिए था। उन्होंने कहा कि कांग्रेस राज्यों के बजट का अध्ययन करेगी और उसके हिसाब से ही ऐलान किया जाएगा कि क्या गारंटी दी जाएंगी। स्वीकार्य हो कि कांग्रेस और उसके सहयोगी दलों ने महाराष्ट्र का बजट पढ़कर ही ये वादे किये होंगे, लेकिन प्रश्न उपस्थित होता है कि इनमें से कितने वायदों को पूरा किया जायेगा और क्या जनता इन पर विश्वास करेगी भी या नहीं? ज्ञातव्य है कि कांग्रेस के वायदों पर प्रश्न खड़ा करने वाली भारतीय जनता पार्टी भी महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे की माझी लाड़की बहीण योजना पर जबरदस्त बल प्रदान कर रही है। ये वुनावी वायदे हैं या रेवड़ी, यह प्रश्न दो वर्ष पूर्व ही प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने उपस्थित किया था कि जब कांग्रेस ने कर्नाटक, तेलंगाना और हिमाचल प्रदेश के चुनावों में भी महिलाओं और नौजवानों के लिए ऐसे ही वादे किये थे। हिमांचल में कांग्रेस ने दस चुनावी वायदे किये थे। तीना स्थानों पर महिलाओं और नौजवानों को लुभाने के लिए उन्हें हर महीने भत्ता देने का वादा हुआ। कहा जा सकता है कि पार्टी को इसका लाभ भी हासिल हुआ। लेकिन तेलंगाना में केसीआर और आंध्र में जगमोहन रेड्डी अपनी सरकार की उपलब्धियां गिनाते रह गये और वोटरों ने उनका साथ नहीं दिया। जब कि मध्य प्रदेश में भाजपा की जीत में ऐसी ही योजना की बड़ी भूमिका मानी जा री है। राज्यों के चुनाव को छोड़कर भी दें तो देश की राजनीति में किसान सम्मान योजना, मुफ्त रसोई गैस, शैचालय, अनाज योजना ने जो भूमिका निभाई है, उसे भला कैसे नजर अंदाज किया जा सकता है? खरगे की इस बात से किसी को क्या ऐतराज हो सकता है जो भी सुनेगा यही कहेगा कि समझदारी की बात है, राजनीतिक दलों को ऐसा ही करना चाहिए मगर राजनीति ऐसे तो चलती नहीं है। भाजपा ने बात पकड़ ली और स्वयं प्रधानमंत्री मैदान में आ गए। उन्होने कहा कि कांग्रेस की हालत खस्ता कर दी है और सरकार के पास वादे पूरे करने के लिए पैसे नहीं है। हालांकि, कांग्रेस की तरफ से इसका खंडन हो रहा है, लेकिन बाकी देश में यह विवाद छिड़ गया है कि चुनावी वादे जनता की भलाई के लिए हैं या फिर वोट जुटाने के लिए रेवड़ी बाटने की कवायद है। और फिर, महाराष्ट्र चुनाव के लिए महाविकास अघाड़ी यानी कांग्रेस की तरफ से पांच गारंटियों की घोषणाएं भी की जा चुकी हैं। स्वयं राहुल गांधी ने यह घोषित किया है किमहिलाओं के लिए तीन हजार रुपए महीने का भुगतान, और महिलाओं और बच्चियों के लिए मुफ्त बस सेवा देने वाली महालक्ष्मी योजना पहली गारंटी है, दूसरी गारंटी-किसानों के लिए तीन लाख रुपए तक की कर्जमाफी और कर्ज चुकाने वाले किसानों को पचास हजार रुपए की प्रोत्साहन राशि। इसे कृषि समृद्धि कहा का नाम दिया गया है। तीसरी गारंटी-राज्य में जातिगत गणना और आरक्षण में पचास प्रतिशत की सीमा समाप्त करने की घोषणा। चौथी गारंटी है- 25 लाख रुपए तक का स्वास्थ्य बीमा और मुफ्त दवाएं। पांचवा वायदा है- बेरोजगार नौजवानों को प्रतिमाह चार हजार रुपए तक की सहायता। नोबेल विजेता अर्थशास्त्री भी अब यह स्वीकार कर रहे हैं कि आगामी वक्त में सबके लिए काम जुटाना संभव नहीं होगा, ऐसे में सरकारों को न सिर्फ गरीबों को मदद देने, बल्कि बिना उनके आत्मसम्मान को चोट पहुंचाए मदद का इंतजाम करना होगा। केन्द्र अथवा राज्य सरकारों की हालत पर दृष्टिपात करते हैं तो यह पाते हैं कि वे मदद पहुंचाने में अपना भी राजनीतिक लाभ देखने में लगी हुई हैं। सम्मान का सवाल अभी कोसों दूर है।

योगी ने गढ़ी राष्ट्रवाद की नई परिभाषा

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राष्ट्रवाद की नयी परिभाषा दी है। उनके अनुसार जो रामभक्त है वहीं राष्ट्रवादी है। इस परिभाषा को वे अक्सर दोहराते रहते हैं जिससे कि आम जनता यह समझ ले कि राम का नाम लेकर राजनीति करने वाले संघ परिवार तथा भाजपा से जुड़े लोग ही सच्चे रामभक्त व राष्ट्रवादी है तथा विपक्षी दलों के लोग चूंकि न तो अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा में शामिल हुए थे और न बार-बार रामलला के दर्शनों को जाते हैं, इसलिए वे रामद्रोही है। इस तर्क से जो राम होगा वह निश्चित रूप से राष्ट्र विरोधी होगा। इसीलिए भाजपा के नेता विपक्षी दलों के नेताओं पर राष्ट्र विरोधी होने का आरोप लगाया करते हैं।

हिन्दू राम भक्त होते हैं या राम का नाम सम्मान से लेते हैं पर मुस्लिम तथा ईसाई राम का नाम तो आदर पूर्वक लेते हैं पर कुछ अपवाद को छोड़कर उन्हें राम भक्त की संज्ञा नहीं दी जा सकती। इसीलिए योगी आदित्यनाथ का वैचारिक मार्गदर्शक आर.एस.एस. मुसलमान तथा ईसाइयों को तो देश का आन्तरिक शत्रु मानते हैं। संघ के वैचारिक शिखर पुरुष गुरु गोलवलकर मानते हैं कि हिन्दू नाल, हिन्दू धर्म हिन्दू संस्कृति तथा हिन्दी भाषा से राष्ट्र की अवधारणा पूरी होती है। जो लोग राष्ट्रीय यानी हिन्दू धर्म संस्कृति तथा भाषा से सम्बन्धित नहीं है वे स्वाभाविक रूप से वास्तविक राष्ट्रीय जीवन के बाहर रह जाते हैं। हिन्दुस्तान हिन्दुओं का देश है और एक हिन्दू राष्ट्र के फलने-फूलने के लिए धरती है। जो हिन्दू नहीं है, उनके लिए गोलवलकर द्वारा पेश किया गया नुस्खा है। राष्ट्रीय जीवन में तब तक उनके लिए कोई स्थान नहीं हो सकता जब तक वे अपनी भिन्नता को त्याग नहीं देते, राष्ट्र के धर्म तथा उसकी भाषा संस्कृति को नहीं अपना लेते और खुद को राष्ट्रीय नस्ल में पूरी तरह घुलमिल नहीं देते। बहरहाल जब तक वे अपनी नरल, धार्मिक तथा सांस्कृतिक भिन्नताओं को बनाए रखेंगे वे विदेशी के सिवा कुछ नहीं हो सकते।

कांग्रेस को तो आर.एस.एस. शुरू से ही वादी संगठन नहीं मानता था। यह सही है कि राष्ट्रीय आन्दोलन का नेतृत्व कांग्रेस कर रही थी जिसके कारण भारत को आजादी मिली।

महात्मागांधी जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल, लोकमान्य तिलक, डॉ. राजेन्द्र प्रसाद, जयप्रकाश नारायण, राममनोहर लोहिया, सुभाषचन्द्र बोस, जैसे महापुरुषों ने कांग्रेस के तिरंगे झण्डे के नीचे लाठी गोलियां खायी जेलों में गये तथा ब्रिटिश शासन के जुल्मों के शिकार बने।

गोलवलकर को इस बात का दुःख था कि कांग्रेस ने स्वाधीनता आन्दोलन को अग्रेज विरोधी आन्दोलन बना दिया। उनके शब्दों में अग्रेज विरोध ही देशभक्ति का व राष्ट्रीयता का समानार्थी माना गया। इससे हमारे सच्चे राष्ट्रवाद का भाव समाप्त हो गया तथा इसका समाज पर विनाशकारी प्रभाव पड़ा।

अपनी उक्त सोच के कारण ही आर.एस.एस. मे आन्दोलन में भाग नहीं लिया। उसके स्वयं सेवक अंग्रेजी शासकों के विरुद्ध आन्दोलन कर जेल जाने के बजाय हिन्दू एकता हिन्दू राष्ट्र का राग अलापते रहे और ब्रिटिश सरकार की छत्रछाय में अपने संगठन का विस्तार करते रहे। इसी तरह जब तक भारत गुलाम था तब तक मथुरा, काशी, अयोध्या आदि धार्मिक स्थलों में विद्यमान मंदिरों तथा मठों के माधी व पुजारी बैठकर भजन कीर्तन करते रहे तथा राजनीति व राष्ट्रीय आन्दोलनों से दूर रहे कुछ अपवादों को छोड़कर महतों व मठाधीशों का जेल जाने व लाठियां गोलिया खाने का कोई रिकार्ड नहीं है क्यों कि वे धर्म और राजनीति का क्षेत्र अलग-अलग मानते थे।

कांग्रेस के समावेशी राष्ट्रवाद को गुरुगोलवलकर विकृत राष्ट्रवाद की संज्ञा देते हैं क्योंकि वह हिन्दू व मुसलमान दोनों को साथ लेकर चलता था। आर.एस.एस. की समझ से जो लोग मुस्लिम आक्रांताओं के साथ मिलकर आजादी की लड़ाई लड़ना चाहते हैं। वे राष्ट्रीय है। गोलवलकर स्पष्ट लिखते है वे ही आन्दोलन है जिसका लक्ष्य हिन्दू राष्ट्र का पुनर्निर्माण करना, नयी जान डालना उसे अपनी अर्द्धनिद्रा से जगाना है। वे ही राष्ट्रवादी देशभक्त है जो हिन्दू नस्ल तथा राष्ट्र को गौरवान्वित करने की आकांक्षा अपने हृदय में लेकर गतिविधियों के लिए उत्प्रेरित होते हैं। अन्य सभी या तो महार या राष्ट्र लक्ष्य के शत्रु है या दवपूर्ण दृष्टि अपनायी जाय तो कहा जाएगा मंदमति है। इस प्रकार कांग्रेस के झंडे के नीचे लाठी गोली खाने वाले जेल जाने वाले स्वतंत्रता संग्राम सेनानी आर.एस.एस. की दृष्टि में गद्दार थे और अंग्रेजों की छाया में हिन्दू राष्ट्र का प्रचार करने वाले सच्चे देशभक्त थे।

गुरु गोलवलकर विभिन्न भाषा, धर्मों, संस्कृतियों से मिलकर बने भारतीय राष्ट्रवाद की निन्दा करते हैं तथा भारत की मिलीजुली संस्कृति का उपहास करते हैं। वे इसे विकृत राष्ट्रवाद कहते है जिसमें जान फूंकी जा रही है।

यह वैसा ही है जैसे एक बंदर के सिर, बैल के पैर और हाथी के शरीर को मिलाकर एक अभिनव प्राणी तैयार किया जाय। इसका परिणाम सिर्फ एक सड़ी लाश हो सकता है।

गोलवलकर ने पहले तो क्रान्तिकारी आन्दोलन की प्रशंसा की। परन्तु जब क्रान्तिकारी आन्दोलन के नायक-राम प्रसाद विस्मिल, चन्द्रशेखर आजाद, भगत सिंह, राजगुरू, सुखदेव, भगवती चरण वोहरा, आदि का झुकाव समाजवाद की ओर हो गया और वे सोवियत रूस की क्रान्ति व उसकी व्यवस्था की प्रशंसा करने लगे, गोलवलकर उनके कटु आलोचक हो गए। गुरु गोलवलकर के शब्दों में किसी समय जो ज्वलंत देशभक्ति से पूर्ण देशभक्त थे वे आज उसी प्रकार उत्कट परदेश भक्त से गए, कितना घोर पतन है।

आजादी के पहले राष्ट्रीय आन्दोलन से दूरी बनाए रखने वाले आजादी के बाद अपने को सच्चा भक्त कहने लगे। आर.एस.एस. विश्व हिन्दू परिषद की कृपा से बड़ी संख्या में मठाधीश व पुजारी भी राजनीति में कूद पड़े हैं और कई राज्यों में विधायक, मंत्री, सांसद व मुख्यमंत्री तक बन गये हैं। अब उनके लिए धर्म और राजनीति का क्षेत्र अलग-अलग नहीं है बल्कि धर्म के क्षेत्र के मठाधीश ही राजनीति के मठाधीश हो गए हैं और धर्म तथा राजनीति एकाकार हो गयी है। जो अंग्रेजी शासन के भय से

मंदिरों में मठों में घुसे हुए थे वे आज राजसत्ता की ऊंची कुर्सियों तक पहुंच गये हैं और राष्ट्रवाद व देशभक्त की नयी-नयी परिभाषाएं रहे हैं। जिनके डी.एन.ए. में अंग्रेज भक्ति है और वे देशभक्तों के वारिसों के बी. एन. ए. पर प्रश्नचिन्ह लगा रहे है। इन नये किस्म के राष्ट्रवादियों की दृष्टि में छः वर्ष से अधिक ब्रिटिश सरकार की जेलों में रहे चार बार कांग्रेस अध्यक्ष रहे राष्ट्रीय आन्दोलन के महानायक जवाहरलाल नेहरू सच्चे देशभक्त नहीं है। समूचे नेहरू परिवार मोतीलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू कमला नेहरू, विजयलक्ष्मी पंडित, इन्दिरा गांधी आदि ने जेलों की यातनाएं सही पर वह राष्ट्रवादी देशभक्त परिवार नहीं है। उनकी नजर में अपनी जवानी में अंग्रेजों के विरुद्ध संघर्ष करने के बजाय गांव- गांव जाकर हिन्दुओं को संगठित करने वाले दीनदयाल उपाध्याय व अटल बिहारी वाजपेयी ही सच्चे राष्ट्रवादी व देशभक्त है। योगी आदित्यनाथ दूसरे शब्दों में वही बात कह रहे हैं जो कि संघ परिवार पिछले नौ दशकों से कहता आ रहा है। आर.एस.एस. ने हमेशा कांग्रेस की तथा उसके नेतृत्व में चले राष्ट्रीय मुक्ति संग्राम की आलोचना की है तथा देशभक्ति को हिन्दू धर्म के साथ जोड़ा है। संघ परिवार महात्मा गांधी के नेतृत्व में चले राष्ट्रीय आन्दोलन से उपने मूल्यों जिन्हें कि भारतीय संविधान में अंकित किया गया है, को पूरी तरह मिटाना चाहता है। इसीलिए उसकी मूल योजना भारतीय संविधान को ही बदलने की है और वह अम्बेडकर के बनाए संविधान की जगह मनुस्मृति की व्यवस्थाओं को लागू करना चाहता है। भारतीय लोकतंत्र एवं संविधान को बचाने के लिए इस नयी परिभाषा की असलियत को समझना होगा।

घूँघट की बगावत

17 नवम्बर 2024

प्रत्येक रविवार को प्रकाशित
हिन्दी साप्ताहिक समाचार पत्र

अपने ही जब डूबती नैया से कूद जाए...

आजादी के बाद कांग्रेस की नियत अच्छी नहीं रही। जातीय जनगणना का शोर उठाने वाली कांग्रेस भूल गई कि उसे यह पहचान दिलाने वाले ब्राह्मण वर्ग के लोग थे, जिन्होंने शुरूआती दौर में कांग्रेस को आँख बंद करके समर्थन दिया। तब जब संघ प्रकाश में आया तब सत्ता में बैठे मठाधीशों को प्रॉब्लम होने लगी, उन्होंने इस जाति आरक्षण को ढाल बनाया और अब के जनगणना के असली उद्देश्य को गुमराह करने की मुहिम चलानी शुरू कर दी, इस मुहिम को सफल बनाने के लिए उन्हें चाहिए था ईंधन खुराक, उन्होंने इसके लिए मुस्लिमों का खौफ दिखाना शुरू कर दिया। बटेंगे तो कटेंगे का वास्तविकता कुछ और दुष्प्रचार कुछ और जबकि मुस्लिम वोटर जानते है की भाजपा से ज्यादा खतरा कांग्रेस शासन में है मगर कांग्रेस का बैक ग्राउंड में जो थीम है वह ओबीसी एससी एसटी आदिवासी के खिलाफ है। जाति जनगणना होने पाए यह केवल सवर्ण चाहते है , सभी जातियों को बराबर हक और अधिकार मिलने पाए यह केवल भाजपा चाहती है , सभी को रोजगार सत्ता और सम्मान मिलने पाए यह पीएम मोदी का विजन हो इसके लिए उन्होंने सॉफ्ट ट्रिक बनाया है, बंटेंगे तो कटेंगे कुछ और नहीं बल्कि ओबीसी एससी एसटी और आदिवासियों की एकता को जोड़ने का एक मंत्र हो जिसे षणयंत्र का नाम देकर कांग्रेस अब बैक फूट पर है। कांग्रेस के अनुसार इस षणयंत्र का मुख्य उद्देश्य जातिय जनगणना को रोक कर सदियों से चली आ रही जातिय भेदभाव, शोषण और जुल्म की व्यवस्था को कायम करना है। इसका उद्देश्य सत्ता सरकार और सिस्टम में सभी को बराबरी के हक से वंचित करना है। राहुल कहते फिर रहें कि यह सरकार कांग्रेस की सरकार नहीं है जिसने आपको वोट का अधिकार दिया, यह बीजेपी की सरकार है और यह सरकार संघ के नियमों से चलती है, संघ कभी नहीं चाहेगा कि सत्ता उसके हाथ से बाहर निकले।

सर्वे हो तो पता चल सके की आरक्षण प्राप्त करने वालों में किसे कितना रिसोर्सेज मिला, किसे कितना अवसर मिला, कौन कितना पढ़ा, कितना आगे बढ़ा और किसकी क्या स्थिति है उसका पता लगाया जा सके ताकि खाइयों को भर कर सबका जीवन स्तर ठीक किया जा सके।

इस तरह हम कह सकते हैं कि लोकतंत्र और निष्पक्ष चुनाव की व्यवस्था को डिस्टर्ब करने जो गलती कांग्रेस ने की है, बीजेपी संघ उसे भुनाने की कोशिश करेंगी और अनर्गल बयानबाजी कभी नहीं करेगी। सरकार बनती तो कांग्रेस ने लोकतंत्र का ऐसा सिस्टम बनाता कि वह जिसे चाहता जनता उसे चुनती , जिसे न चाहे उसे सत्ता से बेदखल कर देती। बाद में मंदिर मस्जिद, भारत पाकिस्तान, हिंदू मुस्लिम का राजनीतिक कॉकटेल बना कर कांग्रेस द्वारा ही जनता का ब्रेन वाश किया गया। अब बीजेपी की सरकार है और वह लोकतंत्र को अब स्थिर रखें हुए है। अब इस स्तर पर कोंग्रेस किसी को कभी ईमानदार निष्पक्ष और मजबूत नहीं होने देगी। मोदी का कार्य ऐसा की जनता केंद्र की सरकार बदल सके, जिसे चाहे चुन सके , जिसे चाहे हटा सके। तानाशाही का सबसे वर्स्ट वर्जन आना अभी बाकी है लेकिन दुर्भाग्य से 80% हिंदुओ को अभी से ज्ञान हो गया और सबको हिंदू बन कर एक खास जाति वर्ग की सरकार बनाई जा रही है, लेकिन जातियों के आधार पर जो भेदभाव शोषण हुआ और हो रहा है उस विषय पर कोई बात नहीं कर रहा है। राहुल गांधी ने जाति के आधार पर बनाई गई असमानता की खाई को भरने के लिए वोट बैंक की राजनीति शुरू की , हक और न्याय के लिए नहीं अपितु कुर्सी के लिए जातीय जनगणना की बात कि ताकि जातियों के आधार पर प्राप्त किया गया मलाई खास धर्म में बाँट सकें और जुल्म भेदभाव और शोषण से ग्रसित सवर्ण मुँह ताकतें रह जाए। सर्वे हो तो पता चल सके की आरक्षण प्राप्त करने वालों में किसे कितना रिसोर्सेज मिला, किसे कितना अवसर मिला, कौन कितना पढ़ा, कितना आगे बढ़ा और किसकी क्या स्थिति है उसका पता लगाया जा सके ताकि खाइयों को भर कर सबका जीवन स्तर ठीक किया जा सके।

पंकज सीबी मिश्रा
जौनपुर यूपी

सरकारी अवसरों में कहीं फिट नहीं बैठते बेरोजगार

सरकारी नौकरियों में सरकार ईमानदार नहीं

देश में बेरोजगारी चरम सीमा पर है। सरकार की नजर में यह भले ही न हो क्योंकि केन्द्र और राज्य सरकारें लोगों को रोजगार और नौकरियां देने में असफल साबित हो रही है। सरकारें कहती है कि हम तो रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने का काम कर रहे है। लेकिन जो भी कथित रूप से यह अवसर पैदा किए जा रहे हैं उसके लिए देश के बेरोजगार फिट ही नहीं बैठ पा रहे हैं। इससे स्थिति जहां की तहां रह जाती है यानी ढ़ाक के तीन पात' जैसी ऐसा भी नहीं है कि सरकारी नौकरियां है ही नहीं, कई लाख पद देश भर में खाली पड़े है लेकिन सरकार उन पर भर्ती नहीं करना चाहती है। क्योंकि वह वेतन भत्तों का बोझ नहीं बढ़ाना चाहती है।

एक तरफ तो सरकार सरकारी नौकरियों में बैठे लोगों का सेवा विस्तार करती जा रही है वहीं सरकारी नौकरियों में काम करने वालों के वेतन भत्ते में वृद्धि करती रहती है। महंगाई के अनुरूप उनकी महंगाई बढ़ जाती है। लेकिन इसका प्रभाव उन लोगों पर क्या पड़ रहा है जिनके पास कोई सरकारी नौकरी या रोजगार तक नहीं है। उन्हें भी तो उसी बाजार से रोजमर्रा की सारी चीजें लेनी होती है। किसानों को लें तो उनका सारा मुनाफा विचौलियों के जेब में जाता है वह चाहे मंडी में सब्जी बेचने वाला किसान हो या अनाज लाने वाला किसान। जब किसान की फसल तैयार होती है तो उसे उचित मूल्य नहीं मिल पाता है और जब फसल बाजार में पहुंच जाती है तो उसका दाम बढ़ जाता है। यही कारण है कि सरकारी नौकरियों के लिए लोग भाग रहे है। क्योंकि यदि वह येन केन प्रकारेण चतुर्थ श्रेणी में भी पहुंच गए और शिक्षा-दीक्षा रही तो वे तृतीय श्रेणी में तो रिटायर होने के समय तक पहुंच ही जायेंगे। 58 से लेकर 62 साल तक वे नौकरी करते रहेंगे और बाद में नई पेंशन पुरानी पेंशन वा बिना पेंशन के भी अपना जीवकोपार्जन करने में अन्यों की अपेक्षा सक्षम होंगे। यद्यपि ऐसी स्थिति में उनका जीवनस्तर अति सामान्य हो जायेगा। वहीं यदि कोई रोजगार का प्रयोग सफल हो गया तो उसे इस नौकरी वाले से अधिक लाभ मिल सकता है लेकिन जोखिम इतना अधिक है जिसे हर कोई उठाने में सक्षम नहीं है। यही कारण है कि लोगों को सरकारी नौकरी जिसे कभी बहुत ही हेय दृष्टि से देखा जाता था तब कहा जाता था उत्तम खेती, मध्यम बान, अथम चाकरी, भीखा निदान आज सरकारी नौकरी की चाहत टॉप पर है। क्योंकि वेतन, भत्ते सुविधाएं आकर्षक हो गई है। ऐसे में सरकार भी एक तो चतुर्थ और तृतीय श्रेणी के पदों पर ईमानदारी से भर्ती करना ही नहीं चाहती है और इसके एवज में वह आउटसोर्सिंग संविदा से काम चला रही है जो सबसे अधिक खपत लोगों की हो सकती थी। इससे आउटसोर्सिंग कम्पनियों और इन्हें अवसर देने वाले अधिकारियों की तो पौ बारह हो गई है लेकिन इसके माध्यम से काम करने वालों की स्थिति मजदूरों से भी बदतर । बशर्ते उन पदों पर ऊपर की आमदनी करने का स्रोत सूखा न हो।

सरकारें जानबूझकर ऐसा कुछ छोड़ देती हैं जिससे बेरोजगार और अहं लोग यह समझे कि सरकार उनके लिए बहुत कुछ कर रही है। कोचिंगों में तैयारी कर-करके अपनी उम्र ग दें लेकिन सरकार की नियुक्ति की तिथि ही न आ सके। यदि आ भी जाये तो वह इतने अदालती पचड़े में फंस जाये कि थक हार कर अपनी अहंता की उम्र गवो चुके अपने आप घंट जायें और शेष बचे लोग अदालती कार्यवाहियों, मंत्री मुख्यमंत्री, राजनेताओं के यहां धरना प्रदर्शन, लाठियां खाने में गया है।

सरकारी नौकरी ने वास्तव में उस मुहावरे को भी पीछे छोड़ दिया है कि 'एक अनार सौ बीमार क्योंकि एक पद के लिए आवेदन मंगाइए तो न्यूनतम शिक्षा की अर्हता के बजाय अधिकतम शिक्षा वाले हजारों लोग सामने खड़े होंगे जो अपने आप में नियुक्ति के मानक बनाने वालों के लिए भी जटिल समस्या खड़ी कर दे रहे हैं। ऐसे में अब सरकारों ने यही रास्ता निकाला है कि 'सांप भी मर जाये और लाठी भी न टूटे।

सुप्रीम कोर्ट का फैसला एक नजीर है कि किस प्रकार से बार- चार विज्ञापन और विज्ञापित पद बदले जाते है और जिसका खामियाजा इसके अभ्यर्थियों को उठाना पड़ता है। काश सरकारें ईमानदारी से कार्य करतीं, तो वह स्थिति तो नहीं आती।

सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक फैसले में कहा है कि सरकारी नौकरियों के भर्ती नियमों को बीच में नहीं बदला जा सकता है। जब तक कि मौजूदा नियम या विज्ञापन जो मौजूदा नियमों के विपरीत न हो। मुख्य न्यायाधीश डी.वाई. चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पांच न्यायमूर्ति हृषिकेश रॉय, न्यायमूर्ति पीएस नरसिम्हा न्यायमूर्ति पंकज मिथल और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की पीठ ने कहा है कि भर्ती प्रक्रिया शुरू होने से पहले निर्धारित किए जा चुके नियमों से बीच में छेड़ नहीं की जा सकती। चयन नियम मनमाने नहीं बल्कि संविधान के अनुच्छेद 14 के अनुरूप होने चाहिए। बीच में नियमों में बदलाव करके उम्मीदवारों को हैरान-परेशान नहीं किया जाना चाहिए।

यही कारण है कि सरकारें जानबूझकर ऐसा कुछ छोड़ देती हैं जिससे बेरोजगार और अहं लोग यह समझे कि सरकार उनके लिए बहुत कुछ कर रही है। कोचिंगों में तैयारी कर-करके अपनी उम्र ग दें लेकिन सरकार की नियुक्ति की तिथि ही न आ सके। यदि आ भी जाये तो वह इतने अदालती पचड़े में फंस जाये कि थक हार कर अपनी अहंता की उम्र गवो चुके अपने आप घंट जायें और शेष बचे लोग अदालती कार्यवाहियों, मंत्री मुख्यमंत्री, राजनेताओं के यहां धरना प्रदर्शन, लाठियां खाने में गया है।

ज्यादातर सरकारें चाहे वे सिंगल इंजन की हो या डबल इंजन की वह मूलतः आरक्षण देने की पक्षधर नहीं होती है जिसके लिए उनके प्रिय अधिकारी ऐसे तरीके निकाल देते हैं कि 'तुम भी खुश और मैं भी खुश उत्तर प्रदेश में 69 हजार शिक्षकों की भर्ती का परिणाम एक केस स्टडी हो सकता है कि किस प्रकार से अभी तक लोग इसमें झूल रहे हैं हाईकोर्ट से बार-बार निर्णय आया और देखना है सुप्रीम कोर्ट इसे किस करवट बैठता है। स्थिति तो यह हो गई है कि यदि सरकार हाईकोर्ट के निर्णय को मान ले तो उन सामान्य लोगों के लिए क्या करे जिनकी भर्ती और नौकरी आरक्षित लोगों की कीमत पर कर ली गई है और यह लोग कई वर्षों से नौकरी कर रहे हैं और नौकरी तक न पहुंच पाने वाले लोग लाठी खा रहे है धरना प्रदर्शन में लगे है।

कोटमराजू रामराव : एक संक्षिप्त परिचय

चीराला (आन्ध्र प्रदेश) में 9 नवम्बर 1896 को जन्मे तेलुगु भाषी रा राव ने मद्रास विश्वविद्यालय से 1917 में अंग्रेजी साहित्य से स्नातक परीक्षा पास की और वहीं अंग्रेजी भाषा का अध्यापन भी किया पत्रकारिता में उनका प्रवेश चेन्नई में ब्रह्मसमाज की पत्रिका 'दि ह्यूमेनिटी' से हुआ। फिर आचार्य टी. एल (साधू) वासवानी के दि न्यू टाइम्स (1919) में कराची में उन्होंने कार्य किया। अपने अग्रज संपादक के पुत्र के दैनिक दि सिंध आजवर में सह- संपादक बने। चार दशक के अपने पत्रकारी जीवन में रामा राव ने दो विश्व युद्धों के दौर की घटनाएँ गाँधी-नेहरू युग का स्वाधीनता संघर्ष और स्वातंत्रयोत्तर भारत में आर्थिक नियोजन, निर्गुट विदेश नीति तथा मीडिया आधुनिकीकरण को देखा और उन पर लिखा।

महात्मा गाँधी के सानिध्य में रहकर (1942-45) रामा राव ने दो दर्जन से ज्यादा भारतीय तथा अन्तर्राष्ट्रीय पत्र-पत्रिकाओं के विशेष संवाददाता के रूप में राष्ट्रीय आंदोलनों की रफ्ट भेजी। केन्द्रीय विधान सभा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशनों तथा राजनीतिक मुकदमों और क्रिकेट टेस्ट मैचों की रिपोटिंग की। उन्होंने बड़ी संख्या में युवा पत्रकारों को प्रशिक्षित किया, जिनमें शाम लाल (जो बाद में टाइम्स आफ इण्डिया के प्रधान संपादक), एच. वाई. शारदा प्रसाद (इन्दिरा गांधी के मीडिया सलाहकार) और एम. चलपति राव जो नेशनल हेरल्ड में तेरहवें स्थान पर आये थे और बाद में सम्पादक बने रामाराव के प्रशिक्षु का नाम था बालकृष्ण मेनन जो सन्यास लेकर स्वामी चिन्मयानंद सरस्वती कहलाए।

सन् 1942 में रामा राव को दि नेशनल हेराल्ड में जेल या जंगल शीर्षक के संपादकीय लिखने पर ब्रिटिश हुकूमत ने छह माह का कारावास और जुमार्ना की सजा दी थी। इस संपादकीय में उन्होंने लखनऊ कैंप जेल में कांग्रेसी सत्याग्रहियों पर हुए बर्बर अत्याचार की भर्त्सना की थी। अवध चीफकोर्ट के निर्णय को आधे घन्टे में रेडियो बर्लिन ने प्रसारित कर दिया था। लखनऊ जेल के क्रान्तिकारी वार्ड में रामा राव को नजरबंद रखा गया, जहाँ उनके पूर्व मोतीलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू, आचार्य जे. बी. कृपलानी, आर. एस. पण्डित (पं. नेहरू के बहनोई) आदि कैद थे। रामा राव के जेल के साथियों में थे भगत सिंह वाले लाहौर षड्यंत्र केस के क्रान्तिकारी शिव वर्मा तथा जयदेव कपूर, कम्युनिस्ट काली शंकर, विप्लवी जोगेश चटजी और लोहियावादी गोपाल नारायण सक्सेना।

प्रख्यात सम्पादक, जानेमाने स्वाधीनता सेनानी और प्रथम संसद (राज्य सभा के सदस्य (1952), कोटमराजू रामा राव अपने दौर के अकेले ऐसे पत्रकार थे, जो 25 से अधिक समाचार-पत्रों में कार्यशील रहे। इन पत्र- पत्रिकाओं में अविभाजित भारत के लाहौर से प्रकाशित (लाला लाजपत राय का) दि पीपुल (1936), कराची का दैनिक दि सिन्ध आजवर (1921), मुम्बई का दि टाइम्स आफ इण्डिया (1924) चेन्नई का दि स्वराज्य (1935), कोलकाता का दि फ्री इण्डिया (1934), नई दिल्ली का दि हिन्दुस्तान टाइम्स (1938) इलाहाबाद के दि लीडर (1920) और दि पायोनियर (1928) तथा पटना का दि सर्चलाइट दैनिक (1950) थे किन्तु रामा राव को ऐतिहासिक ख्याति मिली जब उन्होंने जवाहरलाल नेहरू के दैनिक दि नेशनल हेरल्ड (1938-1946) का लखनऊ में सम्पादन किया ढेर सारे अखबार बदलने पर रामा राव के एक साथी ने टिप्पणी की 'वे अपने एक जेब में संपादकीय की प्रति और दूसरे में त्यागपत्र रखते थे।'

भारत के प्रथम प्रधानमंत्री की यूरोप, अफ्रीका और अमरीका यात्रा (1949) पर रामा राव दि हिन्दुस्तान टाइम्स रूप (इलाहाबाद के दि लीडर तथा पटना के दि सर्चलाइट दैनिकों) के विशेष प्रतिनिधि के नाते गये। संयुक्त राष्ट्र अमेरीका के अलावा रामा राव ने ब्रिटेन, फ्रांस, इटली, मिस्र, कनाडा, ब्राजील, ग्रीस (यूनान), स्विटजरलैण्ड आदि देशों की बत्रा भी की।

रामा राव प्रथम राज्य सभा (1952) के लिये अविभाजित मद्रास राज्य (आन्ध्र प्रान्त) से कांग्रेस के प्रत्याशी के रूप में निर्वाचित हुए। इनके नाम का प्रस्ताव विधायक के. कामराज तथा नीलम संजीव रेड्डी ने किया था। दोनों बाद में कांग्रेस अध्यक्ष बने भारत सरकार के प्रथम सलाहकार (1956) के नाते रामा राव ने पंचवर्षीय योजना के प्रचार-प्रसार का संचालन किया था।

भारत
INDIA
2.00
के.रामा राव K. RAMA RAO

कई पुस्तकों के लेखक, रामा राव ने अपनी आत्मकथा दि पैन एज माई स्वोर्ड लिखी। अखिल भारतीय समाचारपत्र संपादक सम्मेलन (आल इण्डिया न्यूजपेपर एडिटर्स कान्फ्रेंस, 1940) के संस्थापकों में रामा राव थे। देश के सम्पादकों ने मुम्बई में 1942 में हुए अपने आल इण्डिया न्यूजपेपर एडिटर्स कान्फ्रेंस के अधिवेशन में राष्ट्रीय कार्यकारिणी के लिए रामा राव का लखनऊ जेल में कैद रहते ही निर्वाचित किया था। भारतीय श्रमजीवी पत्रकार फेडरेशन (इण्डियन फेडरेशन आफ वर्किंग जर्नलिस्ट्स) के उपाध्यक्ष (1950) को भूमिका में उन्होंने फेडरेशन के संविधान की रचना की श्रमजीवी पत्रकारों के देश-विदेश के अधिवेशनों में शिरकत की प्रथम भाषाई राज्य आंध्र के निर्माण हेतु जनान्दोलन में सक्रिय रहे।

रामा राव के पिता कोटमराजू नारायण राव संस्कृत के पंडित तथा स्कूल के हेडमास्टर (1898) थे उनकी माँ कायम्मा ने ब्रिटिश कलक्टर (सुंदर जनपद) के विरुद्ध 1899 में असहयोग करने और टैक्स न देने हेतु ग्रामवासियों को संगठित किया था। उनके चचेरे भाई कोटमराजू 'बोम्बू' रामव्या आंध्र के प्रथम क्रान्तिकारी थे, जिन्होंने 1910 में कलेश्वर (तेनाली में बम बनाया था।

रामा राव ने अंग्रेजी भाषा की कवयित्री और ज्योतिषी सरसवाणी से सागरतटीय मछलीपत्तनम नगर (आन्ध्र प्रदेश) में 1922 में विवाह किया। इस पाणिग्रहण कार्य को मछलीपतनमवासी, बाद में कांग्रेस अध्यक्ष, स्वतंत्रता सेनानी और मध्य प्रदेश के राज्यपाल स्व. डॉ. बी. पट्टाभि सीतारामल्या ने सम्पन्न कराया था। रामा राव के श्वसुर प्रो. चोहर जाधव टीचर्स ट्रेनिंग कालेज के प्रिंसिपल थे। रामा राव के चार पुत्रों में प्रथम प्रताप भारतीय विदेश सेवा से रिटायर होने पर अमरीका में बस गये थे।

दूसरे नारायण भारतीय आडिट एवं अकाउन्ट्स सर्विस से रिटायर होकर अब नई दिल्ली में त्रैमासिक जर्नल ऑफ एस्ट्रोलोजी के संपादक हैं। तृतीय विक्रम लखनऊ में श्रमजीवी पत्रकार है। आखिरी सुभाष पूर्व राष्ट्रीयकृत बैंक मैनेजर थे चार पुत्रियों में ज्येष्ठ वसंत तथा कनिष्ठ हेमन्त अमरीका में बस गई। द्वितीय, शरद तथा तृतीय, शिशिर दोनों ने ही भारतीय सेना के अधिकारियों से विवाह कर कानपुर तथा बेंगलूर में बसी।

मनोरंजन, हॉरर, कॉमेडी और ट्विस्ट से भरपूर मूवी भूल-भुलैया-3

कार्तिक आर्यन, त्रिपती डिमरी, माधुरी दीक्षित नेने और विद्या बालन-स्टारर भूल भुलैया 3 अपने पहले ट्रेलर के अनावरण के बाद से 2024 की बहुप्रतीक्षित फिल्मों में से एक है, जिसमें रूह बाबा और दो मंजुलिका की लड़ाई दिखाई गई है। अगर आप भी इस बात को लेकर असमंजस में हैं कि इस दिवाली कौन सी फिल्म देखें, भूल भुलैया 3 या सिंघम अगेन, तो कार्तिक आर्यन-स्टारर की यह विस्तृत समीक्षा पढ़ें और जानें कि यह आपके समय के लायक है या नहीं।

कहानी- भूल भुलैया 3 की कहानी 200 साल पहले शुरू होती है, जिसमें मंजुलिका को रक्तघाट के राजा द्वारा मौत की सजा दी जाती है। इसके बाद कहानी वर्तमान में आती है, जहां रूह बाबा (कार्तिक आर्यन) और उसका साथी कोलकाता में भूत भगाने वाले बनकर लोगों को ठग रहे हैं। फिर मीरा (तृप्ति डिमरी) और राजेश शर्मा (मीरा के चाचा) रूह बाबा से मिलते हैं और उसे अपने साथ रक्तघाट आने के लिए कहते हैं और मंजुलिका से शहर और उनके किले को बचाने का नाटक करते हैं, ताकि वे किले को बेच सकें। जैसा कि ट्रेलर में दिखाया गया है, इस बार रूह बाबा को मंजुलिका की दोहरी मुसीबत का सामना करना पड़ेगा। फिल्म का मुख्य कथानक इन कथानकों के इर्द-गिर्द घूमता है, कैसे रूह बाबा असली मंजुलिका को ढूंढता है और कैसे वह रक्तघाट को उसके प्रकोप से बचाता है। चाहे आप कहानी के बारे में कितना भी अनुमान लगाने की कोशिश करें, लेकिन फिल्म में आने वाले उतार-चढ़ाव आपको चौंका देंगे।

अभिनय-अभिनय के मामले में, न केवल मुख्य कलाकार बल्कि राजेश शर्मा, विजय राज, संजय मिश्रा, राजपाल यादव, अश्विनी कालसेकर और अरुण कुशवाह जैसे सहायक कलाकार भी आपको पूरी फिल्म में प्रभावित करेंगे। भूल भुलैया 3 की कहानी मुख्य रूप से कार्तिक, त्रिपती, विद्या और माधुरी के किरदारों के इर्द-गिर्द घूमती है, जो मुख्य रूप से फिल्म के रोमांच और डरावने पहलुओं पर केंद्रित हैं। वहीं, राजपाल यादव, राजेश शर्मा, विजय राज, अश्विनी, अरुण और संजय मिश्रा के किरदार जब भी स्क्रीन पर आएंगे, आपको गुदगुदाएंगे। कुल मिलाकर, अभिनय के लिहाज से फिल्म आपको निराश नहीं करेगी और इन किरदारों ने हॉरर और कॉमेडी का बेहतरीन मिश्रण तैयार किया है।

संगीत-भूल भुलैया 3 में एकमात्र हिस्सा जो आपको प्रभावित नहीं करेगा, वह है इसके गाने। पूरी फिल्म में प्रतिष्ठित 'अमी जे तोमर' के अलग-अलग वर्जन के अलावा, आपको फिल्म के बाद एक भी ट्रैक याद नहीं रहेगा। इतना ही नहीं, फिल्म के कुछ गाने अप्रासंगिक लगे और उन्हें टाला जा सकता था। हॉरर सीन के दौरान बैकग्राउंड स्कोर दस-दस हैं।

निर्देशन- अनीस बज्मी ने एक बार फिर निर्देशक के तौर पर अपनी भूमिका से अपनी काबिलियत साबित की। उन्होंने फिल्म की कहानी के हिसाब से सभी किरदारों का बखूबी इस्तेमाल किया और इस बेहतरीन कलाकार ने भी स्क्रीन पर अपनी मौजूदगी से निराश नहीं किया। भूल भुलैया 3 कई ट्विस्ट से भरी है, चाहे इंटरवल से पहले का पहला भाग हो या इंटरवल के बाद का। फिल्म दर्शकों को बस यह सोचने पर मजबूर करती है कि असली मंजुलिका कौन है और इस रक्तघाट की शैतान की कहानी का अंत कैसे होता है।

फैसला-उल्लेख्य है भूल भुलैया 3 ट्विस्ट से भरी है और इसका अपने पिछले संस्करणों से कोई लेना-देना नहीं है। इस फिल्म की कहानी अपने पिछले संस्करणों से बिल्कुल अलग है, लेकिन मुख्य प्रतिपक्षी के रूप में मंजुलिका के इर्द-गिर्द घूमती है। अगर आपको लगता है कि अनीस बज्मी ने थोड़े हास्य के साथ एक साधारण हॉरर कॉमेडी को बड़े पर्दे पर पेश किया है, तो इस बार ऐसा नहीं है। क्लाइमेक्स में, फिल्म निश्चित रूप से आपको एक बड़े ट्विस्ट से चौंका देगी।

स्वामी/मुद्रक/प्रकाशक पंकज धर द्विवेदी द्वारा जनप्रकाशन प्रेस निकट रीड्स साहब का
धर्मशाला से मुद्रित एवं 45, बादशाह बाग, जगन्नाथपुर, गोरखपुर से प्रकाशित।
संपादक: पंकज धर द्विवेदी
संपर्क सूत्र : ghoonghatkibagawat37@gmail.com